।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-2
● अंक-236
रायपुर, गुरुवार 25 मई 2023
● पृष्ठ-6
● मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

19 दल संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करेंगे

नया संसद भवन कांग्रेस की ही सोच, अब बहिष्कार क्यों : आज़ाद

नयी दिल्ली। कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दलों ने बुधवार को कहा कि वे संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का सामूहिक बहिष्कार करेंगे क्योंकि इस सरकार में संसद से लोकतंत्र की आत्मा को निकाल दिया गया है। उन्होंने एक संयुक्त बयान में यह आरोप भी लगाया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन समारोह से दरकिनार करना और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संसद के नए भवन का उद्घाटन करने का फैसला लोकतंत्र पर सीधा हमला है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, समाजवादी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय जनता दल और कई अन्य विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी किया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंग

स्पीकर करे नए संसद भवन का उद्घाटन:ओवैसी

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसको लेकर अलग मांग रख दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी मांग में कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की जरूरत है इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता लेकिन इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने हमारी पार्टी से संपर्क नहीं किया है। उद्घाटन लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए क्योंकि वह संसद के अभिरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। अगर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं करेंगे तो हम समारोह में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं की आप पीछे हट जाइए और स्पीकर ओम बिड़ला को उद्घाटन करने दें।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि नई संसद के उद्घाटन में देश की राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित करना..ये आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज का अपमान है और ये प्रदर्शित करता है कि बीजेपी की मानसिकता आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है, वरना संसद के उद्घाटन में अगर आप राष्ट्रपति को ही नहीं बुला रहे हैं तो फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं?

बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सभी लोगों से बात हुई है हम लोग इसका बहिष्कार करेंगे। हम लोगों का मानना है कि नए संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा होना चाहिए क्योंकि

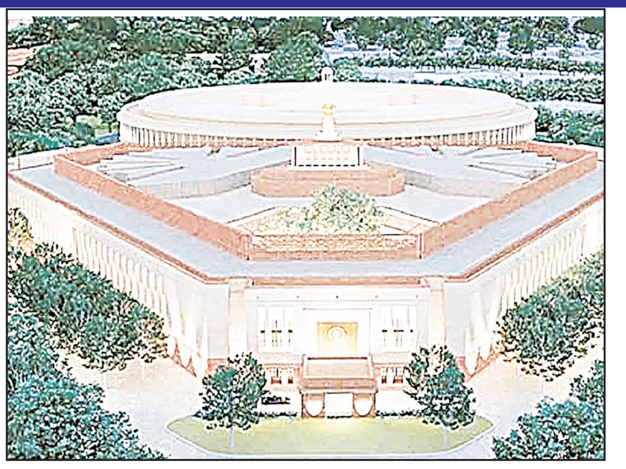

संसद का हेड राष्ट्रपति होता है और ये उद्घाटन उनसे न कराकर उनका अपमान किया जा रहा है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि यह (पुराना) संसद भवन ऐतिहासिक है और इस संसद भवन से न ऋस्स और न भाजपा का कोई रिश्ता है। यह खर्चा सिर्फ शिला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा का उद्घाटन किया गया लिखाए जाने के लिए हो रहा है। संविधान के अभिरक्षक राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा।

डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज से 23-32 वर्ष पहले जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब शिवराज पाटिल ने कहा था कि 2026 से पहले नया और बड़ा संसद भवन बनना चाहिए क्योंकि 2026 तक अंकुश लगा है कि संसद की सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती हैं। जहां तक नया संसद भवन बनाने की बात है तो यह नई बात नहीं है यह 32 साल पहले कांग्रेस की ही सोच थी। ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अब कोई इसका बहिष्कार करता है, नहीं जाता है तो इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी होती तो उसे इसे बनान ही पड़ता। विपक्ष द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विपक्ष की तरफ से एक निराधार बहस उठाने का काम किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इनके शासन काल में इनके प्रधानमंत्रियों के द्वारा ऐसे उद्घाटन नहीं हुए।

ये सभी दल समारोह से दूर रहेंगे

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस,द्रविड मुन्नेत्र कड़गम,जनता दल ,,आम आदमी पार्टी ,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी,शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे),मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी,समाजवादी पार्टी,राष्ट्रीय जनता दल,भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग,झारखंड मुक्ति मोर्चा,नेशनल कांफ्रेंस,केरल कांग्रेस (मणि),रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी,विदुथलाई चिरुथिगल काट्ची (वीसीके), मारुमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कड़गम (एमडीएमके),राष्ट्रीय लोकदल

कार्यक्रम में शामिल होंगे ये दल

बीजू जनता दल,बहुजन समाज पार्टी,टीडीपी,वाईएसआर कांग्रेस,,एआईडीएमके,अकाली दल।

रिकॉर्ड समय में बना नया संसद भवनः शाह

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के नौ साल पूरे होने पर मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए, अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी 28 मई को नए संसद भवन को देश को समर्पित करेंगे।अमित शाह ने कहा,नए संसद भवन का निर्माण रिकॉर्ड समय में किया गया है और पीएम इसे बनाने वाले 60,000 श्रमिकों को सम्मानित और सम्मानित करेंगे। पीएम मोदी जी 28 मई को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।संसद का यह नया भवन प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का प्रमाण है।अमित शाह ने कहा, नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का यह एक सुंदर प्रयास है। इस संसद भवन के रिकॉर्ड समय के निर्माण में लगभग 60,000 श्रम योगियों ने योगदान दिया है। अमित शाह ने आगे कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ लक्ष्य तय किए थे, उसमें एक लक्ष्य हमारी ऐतिहासिक परंपराओं का सम्मान और उनका पुनर्जागरण भी था। एक प्रकार से नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शिता का प्रमाण है। जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है।

इन दिनों

के सी त्यागी

कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए

कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की एकता को बल मिला है। राज्य में कांग्रेस की यह सबसे बड़ी जीत कही जा सकती है क्योंकि उसे 1989 के बाद से सबसे अधिक 42.9 प्रतिशत वोट मिला है, वहीं भाजपा ने 36 प्रतिशत वोट ही प्राप्त किया है। कांग्रेस की तरफ से सामाजिक न्याय के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने से जनता ने उसे शानदार बहुमत देकर भाजपा को एक सबक देने की कोशिश की है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय की बैटिंग करके कांग्रेस के पुराने चरित्र को बदलने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसा इस चुनाव से शुरू किया गया है, बल्कि इसकी नींव रायपुर में कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए कांग्रेस प्रतिनिधियों और सभी पदों पर 50 फीसदी आरक्षण की घोषणा के रूप में पड़ी थी। इस मुद्दे को तब और बल मिला, जब 'मोदी सरनेम' वाले बयान पर राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का अपमान करने का दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनायी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गयी। भाजपा ने राहुल गांधी पर ओबीसी के अपमान को लेकर हमले किये और इसी हमले को कांग्रेस ने कर्नाटक में सियासी हथियार बनाया। राहुल गांधी ने अपनी चुनावी सभाओं में जातिगत जनगणना की मांग कर 'जितनी आबादी, उतना हक' की वकालत कर इस नारे को असमानता से जोड़ने का सफल प्रयास किया। ठीक ऐसा ही नारा समाजवादी नेता डॉ राममनोहर लोहिया देते थे- 'पिछड़ा पावे सौ में साठ' यानी राजनीति में हिस्सेदारी हो या संसाधनों पर अधिकार, पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 60 फीसदी होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम का नारा था- 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामाजिक न्याय और समता के सवाल एक बार पुनः राष्ट्रीय राजनीति के विमर्श बदल रहे हैं। सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। बिहार में हो रहे जातिगत सर्वेक्षण को पटना उच्च न्यायालय ने रोक दिया है, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे ने संपूर्ण विपक्ष को एक मंच पर लाने का काम अवश्य किया है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव को सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ने की जमीन भी कर्नाटक चुनाव ने तैयार कर दी है। इन मुद्दों के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं। विभिन्न राज्यों के लगभग एक दर्जन से अधिक क्षेत्रीय पार्टियां जातिगत जनगणना कराने की मांग लंबे समय से कर रही हैं। इनमें डीएमके, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, जेडीयू आदि प्रमुख हैं। देश में 1931 से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की जाति की गणना होती आ रही है, इसलिए शेष जातियों की गणना भी बहुत जरूरी है। यदि कोई जाति सामाजिक संरचना में वंचना का शिकार है, तो उसे मुख्यधारा में लाने के लिए अतिरिक्त अवसर मुहैया कराया जाना चाहिए। ओबीसी वर्ग में कई जातियों को लंबे समय से सामाजिक अन्याय का शिकार होना पड़ा है।

जी20 कार्य समूह की बैठक संपन्न

श्रीनगर। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के जी20 समूह की तीसरी टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक बुधवार को श्रीनगर में संपन्न हुई। प्रतिनिधि बारिश के बीच दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर गए। डल झील के तट पर निशात गार्डन और रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स का दौरा करने से पहले लगभग 60 विदेशी प्रतिनिधियों ने दिन की शुरुआत ज़बरवान पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि में योग सत्र के साथ की।

बड़ा नक्सली हमला नाकाम, 50 किलो आईईडी बरामद

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों ने बड़े हमले की साजिश रची थी। हालांकि समय रहते जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। जवानों ने 50 किलो आईईडी बरामद किया है। इसे सड़क से पांच फीट नीचे फॉक्स होल बनाकर दबाया गया था। सीरीज में जुड़े इन विस्फोटकों में अगर ब्लास्ट होता तो बड़ा नुकसान हो सकता था। करीब एक महीने पहले 26 अप्रैल को भी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर में इसी तरह से ब्लास्ट किया था। उसमें भी 50 किलो आईईडी का इस्तेमाल हुआ। हमले में 10 जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक, थाना आवापल्ली से

बुधवार को सीआरपीएफ 168 और 222वीं बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इस दौरान आवापल्ली-बासागुड़ा मार्ग पर दुर्गा मंदिर के पास जवानों ने आईईडी बरामद की। नक्सलियों ने बीच सड़क पर आठ फीट लंबाई-चौड़ाई और पांच फीट गहराई में फॉक्स होल बनाया था। इसमें 25-25 किलो के आईईडी विस्फोटक दो प्लास्टिक कंटेनर में सीरीज से लगाए गए थे। जवानों ने मौके पर ही इसे सर्चिंग के दौरान पकड़ लिया और बीडीएस की टीम ने इसे निष्क्रीय कर दिया।

एक दिन पहले ही मंगलवार को छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर जवानों ने 10 नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से ट्रैक्टर भरकर विस्फोटक बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक भरकर बड़े माओवादी लीडरों के पास ले जाया जा रहा था। यह भी सामने आया है कि इस विस्फोटक का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ या फिर तेलंगाना में हमले के लिए होना था। यह इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले की तैयारी मानी गई। पकड़े गए नक्सलियों में पांच बीजापुर के रहने वाले थे।

करीब एक माह पहले 26 अप्रैल को नक्सलियों ने दंतेवाड़ा के अरनपुर में हमले को अंजाम दिया था। उस दिन भी बुधवार था और 50 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था। इसमें तीन हेडकांस्टेबल सहित 10 जवान शहीद हुए थे। जबकि एक नागरिक की भी मौत हो गई थी।

प्रमुख समाचार

खास होने वाली है महाकुंभ 2023 की थीम

लखनऊ। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ मेला-2025 को भव्य बनाने के लिए सीएम योगी ने विभागीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि महाकुम्भ मेला-2025 का लोगो और थीम जल्द से जल्द बना लिया जाए। साथ ही, प्रयागराज में पर्यटन विभाग द्वारा विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के अलावा इसके प्रचार-प्रसार और आने वाले भक्तों के लिए नागरिक सुविधाओं का विकास करने पर जोर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि योगी सरकार हर बार की तरह 2025 में होने जा रहे महाकुंभ को भी वृहद स्तर पर आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाकुंभ-2025 में देश और दुनिया से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की बुनियादी जरूरतों के साथ ही सरकार उन्हें भव्य और दिव्य महाकुंभ का दर्शन भी कराएगी।

कर्नाटक से हिजाब पर प्रतिबंध भविष्य में हटाएगी कांग्रेस

बेंगलुरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से लगभग एक साल पहले, सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान (भाजपा सरकार) द्वारा राज्य के शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने से हिजाब विवाद शुरू हो गया था। अब जब से कर्नाटक में सरकार बदली है और कांग्रेस सत्ता में आई है, कई वर्ग प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच कर्नाटक के मंत्री डॉ जी परमेश्वर का बयान सामने आया है। एमनेस्टी इंडिया द्वारा कर्नाटक में हिजाब प्रतिबंध को वापस लेने की मांग पर सवाल का जवाब देते हुए जी परमेश्वर कहा कि सरकार इसे भविष्य में देखेगी। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। अभी हमें कर्नाटक के लोगों से की गई पांच गारंटियों को पूरा करना है। 5 फरवरी, 2022 को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा कि शिक्षण संस्थानों में ड्रेस अनिवार्य रूप से पहनी जानी चाहिए और हिजाब पहनने के लिए कोई अपवाद नहीं बनाया जा सकता है। इस कदम से मुस्लिम समुदायों में भारी आक्रोश पैदा हुआ।

मनीष सिसोदिया ने लंबित जमानत याचिका वापस ली

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के

समक्ष लंबित अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली क्योंकि उनके द्वारा सामना किए गए एक मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका के संबंध में आदेश सुरक्षित रखा गया है। फरवरी में 2021-22 की आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय उसके खिलाफ मामलों की जांच कर रहे हैं। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया को आम आदमी पार्टी के नेता का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर द्वारा आरक्षित आदेश के बारे में अदालत को बताए जाने के बाद याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

जिस मामले में गई आजम की विधायिकी, उसमें हुए बरी

नई दिल्ली। सपा नेजा आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से बरी कर

दिया गया है। इस मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) की कोर्ट ने 27 अक्तूबर 2022 को आजम खां को तीन साल सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधायिकी चली गई थी। नफरती भाषण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा आजम खां को तीन साल सजा सुनाए जाने के फैसले के खिलाफ उन्होंने सेशन कोर्ट में अपील की थी। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आजम खां को नफरती भाषण देने के आरोप से मुक्त कर दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ट्रायल की कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में 70 पेज में अपना फैसला सुनाया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख भी किया गया है। सेशन कोर्ट के इस फैसले से आजम खां को एक राहत मिली है।

असम-मेघालय सीमा विवाद पर मुख्यमंत्री स्तर की हुई बैठक

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने असम-मेघालय सीमा पर मुख्यमंत्री स्तर की बैठक की। इस बैठक के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि हमने विवाद के 6 क्षेत्रों को सुलझा लिया है। क्षेत्रीय समितियों ने इन 6 क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि जून के महीने में हम विश्वास बहाली के उपायों के लिए कार्बी आंगलोंग और अन्य क्षेत्रों का दौरा करेंगे। हम अन्य 6 विवाद क्षेत्रों को हल करने में सक्षम होंगे। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मतभेदों के 12 क्षेत्र हैं और हमने 6 क्षेत्रों का समाधान किया है। क्षेत्रीय समितियां शेष 6 क्षेत्रों का दौरा करेंगी। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने कहा कि आज हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई। शेष बचे 6 क्षेत्रों के लिए समाधान निकालने की यह शुरुआत है। हमने क्षेत्रीय समितियों को इसका अध्ययन करने को कहा है। हम जल्द ही कोई समाधान निकालने की उम्मीद करते हैं। हमें शांति बनाए रखनी चाहिए।

ब्रांड मोदी को दमदार क्षेत्रीय नेताओं की जरूरत

प्रभु चावला

अगर राजनीतिक दल की आकृति हो, तो उसका चेहरा उसके प्रमुख नेता का, मस्तिष्क केंद्रीय प्रभाव का और धड़ उसके जन-प्रतिनिधियों का होगा। शरीर को सक्रिय और चलायमान रखने वाले पैर व बांहें उसके स्थानीय नेता और जमीनी समर्थक होंगे। चुनाव बाद हुए कर्नाटक भाजपा के परीक्षण से इंगित होता है कि उसके अस्थि-पंजर में दरारें आ गयी हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी, पर दमदार क्षेत्रीय नेता की कमी रही। इस कारण भाजपा 224 में से 66 सीटें ही जीत सकी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वह 170 विधानसभा सीटों पर आगे रही थी, पर इस चुनाव में यह आंकड़ा 65 पर आ गया। इसी अवधि में उसका वोट शेयर भी 52 से घटकर 35 प्रतिशत पर आ गया। विशेषज्ञ आंकड़ों के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं, पर सत्ता के खेल में वे गलत साबित होते हैं। कारण स्पष्ट हैं। कर्नाटक में भाजपा की तुलना में कांग्रेस अधिक एकताबद्ध थी। उसके पास जीतने योग्य उम्मीदवार अधिक थे। भाजपा के पास बेच पाने लायक एक ही चीज थी- ब्रांड मोदी।

कर्नाटक की हार इंगित करती है कि मोदी जैसे चक्रवात के साथ फसल उगाने के लिए धरतीपुत्रों का होना कितना महत्वपूर्ण है। स्थानीय बीज के उगते रहने के लिए मिट्टी की ऊपरी परत

को पलटते रहना जरूरी है। क्षेत्रीय वास्तविकताओं को राष्ट्रीय आख्यान के साथ उगाने में संतुलित अनुपात होना जरूरी है। साल 2014 की ऐतिहासिक जीत के बाद से राजनीतिक चक्र भाजपा के पक्ष में तेजी से घूमता रहा है। उसने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीत हासिल की। महाराष्ट्र में शिव सेना के साथ गठबंधन में उसकी सरकार रही। साल 2019 तक इसने संदेहास्पद विलय और दल-बदल से लगभग 20 राज्यों में सत्ता पायी। सब कुछ ठीक दिख रहा था और मोदी ने बड़े बहुमत से सत्ता में वापसी की। सहयोगियों के साथ भाजपा का लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत है, तो राज्यसभा में उसके लगभग सौ सदस्य हैं। साल 2014 में इन 10 राज्यों में कांग्रेस का शासन था- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड। आज उसके पास केवल हिमाचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक हैं। लेकिन कर्नाटक के परिणामों ने राजनीतिक नक्शे को बड़े पैमाने पर बदल दिया है। कभी दो-तिहाई हिस्से पर पसरे केसरिया पदचिह्न सिमट गये हैं। भाजपा अपने बूते 10 राज्यों में और सहयोगियों के साथ तीन राज्यों में सत्तारूढ़ है।

भाजपा का भौगोलिक वर्चस्व मुख्य रूप से छोटे राज्यों, अधिकतर पूर्वोत्तर में, तक सीमित है। बीते पांच वर्षों में वह हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं पा सकी है। नीतीश कुमार के राजद के साथ जाने से उसने बिहार खो दिया। उसके पास उत्तर प्रदेश जैसा महत्वपूर्ण राज्य है। राज्यों के स्तर पर भाजपा का प्रदर्शन 2014 और 2019 के मोदी की जीतों के अनुरूप नहीं रहा है। देश के लगभग 4200 विधायकों में भाजपा विधायकों की संख्या 2017 के 1358 से घटकर 2023 में 1311 हो गयी। वर्ष 2014 से हुए 56 विधानसभा चुनावों में, कुछ के चुनाव दो या तीन बार भी हुए, भाजपा अपने बूते पर केवल 22 चुनाव जीती है, जबकि छह में गठबंधन में उसकी सरकार है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाताओं ने भाजपा को झटका दिया। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अलावा भाजपा के पास कोई बड़ा राज्य नहीं है। वर्ष 2024 में कांग्रेस से अधिक आधा दर्जन क्षेत्रीय दल उसके लिए चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। सफल नेतृत्व का रहस्य सफल उत्तराधिकारी तैयार करने में है। तीसरी पीढ़ी तैयार न कर भाजपा ने गलती की है। साल 1990 से 2004 के बीच आडवाणी-वाजपेयी की टीम ने विचारधारा और जमीनी काम में दक्ष युवाओं की टोली तैयार की थी। नरेंद्र मोदी, प्रमोद महाजन, शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, वसुंधरा राजे, उमा भारती, बीएस येदियुरप्पा, मदन लाल खुराना, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, नितिन गडकरी, अनंत कुमार आदि ने सरकार एवं पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।राष्ट्रीय स्तर के दो नेताओं की अगुवाई में क्षेत्रीय नेताओं के इस समूह ने पार्टी को एक दशक से कम समय में पांच प्रदेशों से पूरे देश में फैला दिया। मोदी 2014 में भाजपा के पहले देशव्यापी प्रधानमंत्री के रूप में उभरे, जिन्होंने पार्टी को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचा दिया।

जिले के नगरीय क्षेत्रों में गोठान है कि नहीं मुंगेलीवासियों को पता ही नहीं : अरुण साव

■ रेंहुटा जैसे लाखों के सुविधाहीन गौठान एक दिखावा सिर्फ भ्रष्टाचार

मुंगेली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद अरुण साव ने मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के मुंगेली नगर पालिका परिषद के रेहुंटा गौठान में निरीक्षण करके जनता का पंचनामा लिया।

रेहुंटा गौठान में जब प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुँचे उस समय मजदूर पशु आहार टांका आदि का सफाई करते मिले। गायों के विश्राम के लिए शेड बनाया ही नहीं गया था। यहां शेड लगाने की तैयारी की जा रही थी। बकरी मुर्गी शेड बनाया ही नहीं गया था। जबकि गौठानों में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा 14वां वित्त,15वां वित्त, मनरेगा और डीएमएफ जैसे विभिन्न मदों से गांव व क्षेत्र के विकास के लिए भेजी गई राशि को सरपंचों को मजबूर कर दबाव पूर्वक गोठान में जबरन दुरुपयोग करवा के, किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में रेहुंटा गांव वालों के साथ चर्चा की। गांव वालों ने कहा कि मोदी द्वारा भेजे गये जिस पैसे को गांव के बिजली,पानी, स्वच्छता, स्कूल, अस्पताल में खर्च किया जा सकता था,उस पैसे का गौठान के नाम पर दुरुपयोग करके भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 2 रुपये किलो की दर से गोबर को गांव वालों से खरीदने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जितना गोबर खरीदा गया उससे 10 गुना ज्यादा वर्मी कंपोस्ट के नाम पर मिट्टी मुरम युक्त खाद उसी क्षेत्र के किसानों को 10 रुपये प्रति किलो की दर से जबरन सोसायटी के माध्यम से बेचा जा रहा है। जो किसान नहीं लेना चाहता, उसे सोसायटी के अन्य सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया जा रहा है। गोठान निर्माण में भी भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार को साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा नरवा, गरवा, घुरवा,बारी योजना के अंतर्गत गोठान के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार की पोल खोली गई है। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक, प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य गिरीश शुक्ला, राजेंद्र वैष्णव,द्वारिका जायसवाल,प्रेम आर्य, मानिकलाल सोनवानी, दीनानाथ केशरवानी, श्रीकांत पाण्डेय, श्रीमती दुर्गा उमाशंकर साहू,नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह,नगर भाजपा अध्यक्ष राणाप्रताप सिंह,शंकर सिंह,सोम वैष्णव,नितेश भारद्वाज, सुनील पाठक, प्रदीप पाण्डेय, कोटू दादवानी, मुकेश रोहरा, रामशरण यादव,मनोहर मोहले, अश्वनी कश्यप, भूपेंद्र सिंह ठाकुर, अनिल पात्रे, सुनील सोनी, राघवेंद्र सिंह बब्बू, पुरुषोत्तम जायसवाल, मिथिलेश केशरवानी, अमितेष आर्य, यश गुप्ता, राहुल मल्लाह,करण सिंह, रवि साहू आदि उपस्थित थे।

अरुण साव ने अमृत काल के पंच-प्रण के बारे में युवाओं को दी जानकारी

मुंगेली। मुंगेली के बी आर साव स्कूल में आज सांसद अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के अमृतकाल के पंच-प्रण की थीम पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र बिलासपुर के तत्वावधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रंगोली, पेंटिंग, कविता,लेखन, भाषण, सामूहिक नृत्य का आयोजन किया गया। सामूहिक नृत्य देशभक्ति से ओतप्रोत रहा।साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक गीत,कर्मा,पंथी, सहित सामूहिक नृत्य का मनमोहक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिलासपुर सांसद अरुण साव ने महाराणा प्रताप जयंती की शुभकामना देते हुए कहा कि युवाओं को महाराणा प्रताप से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के युद्ध में शामिल चेतक घोड़े व हाथी रामप्रसाद से सीख लेने की बात युवाओं से की। आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के उद्देश्य के बारे में बताया की आजादी के लिए पूरे देश ने क्या कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को संजोए रखना है। युवा उत्सव अमृत काल पंच-प्रण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि पंच -प्रण 1.विकसित भारत का निर्माण 2. गुलामी के हर सोच से मुक्ति3. विरासत पर गर्व4. एकता एकजुटता5. नागरिक कर्तव्य।ये अमृत काल के पंच प्रण है जिसके तहत अंग्रेजों द्वारा दी गई पर निर्भरता को दूर कर आत्मनिर्भर भारत से सराबोर विकसित भारत का निर्माण करना है। हमें ऐसी शिक्षा लेने की जरूरत है जिससे हर गुलामी की सोच से मुक्ति मिले। हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा दी गई हर वर्ग,हर समाज,हर समुदाय को तोड़ने की सीख को दूर करते हुए एकता एकजुटता का परिचय देना है। नागरिकों को अपने कर्तव्य पर अडिग रहना है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष शैलेश पाठक, नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहन मल्लाह,जिला पंचायत सदस्य दुर्गा उमाशंकर साहू, जनपद सदस्य शैलेन्द्र तिवारी, पार्षद जितेन्द्र दावड़ा, मोहन उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। युवा केन्द्र बिलासपुर के सौरभ निषाद की पूरी टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुख्यमंत्री का विरोध करने जा रहे भाजपा के कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार

कोरबा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रवास पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध करने की तैयारी की गई थी। इसके पहले ही पुलिस ने भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर थाना में बैठा दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष डा राजीव सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने दौरे में भाजपा द्वारा विरोध किए जाने के डर से पुलिस को आगे कर दिया। इससे भाजपा के कई नेताओं को गिरफ्तार कर जिले के अलग-अलग थानो में बैठा दिया गया।

भाजपा जिला अध्यक्ष डा राजीव सिंह, रामपुर थाने में गिरफ्तार किए गए भाजयुमो जिलाध्यक्ष पंकज सोनी व रजगामार चौकी में गिरफ्तार किए गए लक्ष्मी श्रीवास व धनंजय चौहान से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चार साल के शासन में कोई भी जनउपयोगी कार्य नहीं गिना सकते है। वह जान चुके हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें निकालने वाली है और यह भय उन्हें अब तानाशाह बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। यही कारण है कि अपने दौरे के पहले उन्होंने तानाशाही करते हुए भाजपा नेताओं के विरोध के पहले ही गिरफ्तार करा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ने अब अपना मन बना लिया है, इससे आने वाले विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल की विदाई तय है। जिला अध्यक्ष डा सिंह ने कहा कि सिविल लाइन रामपुर में कोरबा जनपद के उपाध्यक्ष विक्की कंवर को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर बैठा दिया। तो यह बात आसानी से समझ में आ जाती है कि भूपेश बघेल का अपने कांग्रेस के नेताओं से भी विश्वास उठ गया है, जो उनकी बड़ी हार का एक और कारण बनेगा।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज सोनी को उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान से ही पुलिस द्वारा उठाकर सिविल लाइंस थाने में बैठाया गया। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष पंकज सोनी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दमनात्मक रवैया अपना रहे हैं। विपक्ष में रहने वाली राजनीतिक पार्टियां अगर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध ना करें तो जनता की मांगों को किस प्रकार से उठाएं इसका जवाब भूपेश बघेल को देना चाहिए।

काला झंडा दिखाने कुदमुरा जा रहे भाजपा युवा नेताओं को रास्ते से ही गिरफ्तार कर पुलिस करतला थाना ले गई। इसमें भाजपा उरगा मंडल के महामंत्री हरीश साहू, भाजयुमो प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अरविंद भगत व अजय कंवर, भाजयुमो उरगा मंडल अध्यक्ष किशन साव, भाजयुमो मंडल महामंत्री शुभम हलवाई, अजा मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश अनंत, अशोक प्रजापति, अशोक कंवर, यशवंत चौहान, शिरीष कैवर्त, साहिल समेत अन्य कार्यकर्ताओं को करतला थाना में बैठाया गया। वही भाजपा कुदमुरा मंडल के अध्यक्ष लक्ष्मी श्रीवास,युवा मोर्चा कुदमुरा मंडल अध्यक्ष धनंजय चौहान आदि को रजगामार चौकी में सुबह से लेकर कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद तक पुलिस द्वारा बैठा कर रखा गया ।

झूठे आरोप लगाकर बदनाम करने का प्रयास है विधायक बेंजाम पर: कांग्रेस

जगदलपुर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जिला महामंत्री सुन्दर सोढ़ी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी विगत कुछ दिनों से जिम के सामान की खरीदी को लेकर लगातार चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम पर झूठे आरोप लगाकर स्वच्छ एवं ईमानदार छवि को बदनाम कर जनाधार कम करने का प्रयास कर रही है। भाजपा और आप पार्टी के द्वारा विधायक चित्रकोट पर लगाये जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद और झूठ बताते हुए बताया कि विधायक राजमन बेंजाम अपने कार्यालय में रहकर जन सेवा का कार्य करते हैं। सुरक्षा को देखते हुए वे रात्रि विश्राम भी कार्यालय भवन में करते हैं। कार्यालय में भी इतनी पर्याप्त स्थान नहीं है की जिम स्थापित किया जाये। विधायक राजमन बेंजाम के ऊपर जो झूठे आरोप भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया गया है, चित्रकोट की जनता बेबुनियाद और झूठे आरोपों के लिए इन तथाकथित नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी।

जारी विज्ञप्ति में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चन्द्रशेखर ठाकुर ने बताया कि विधायक राजमन बेंजाम के निवास में छात्रावास के जिम का कोई भी सामान नहीं है। जिम के लिए आबंटित सारी सामग्रियों को वर्ष 2020 में ही छात्रावास के जिम कक्ष में स्थापित किया गया है। विधायक राजमन बेंजाम के ऊपर जिम सामग्री के चोरी एवं जिम सामग्रियों को निवास गृह पर रखे जाने जैसे संगीन आरोप सरासर झूठे हैं। जिम सामग्रियों की खरीदी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा किया गया है एवं जिम की सारी सामग्रियों को छात्रावास अधीक्षक को सौपा गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी के द्वारा विधायक के घर जिम सामग्री रखने का आरोप झूठा है। विधायक बेंजाम का निवास 4×6 साइज के 02 कक्ष, एक किचन और एक हॉल से बना हुआ है जिसमें वे अपने परिवार के साथ रहते हैं जहां पर जिम सामग्री रखने का सवाल ही नहीं हैं।

कोरबा लोकसभा की आवाज बनीं सांसद ज्योत्सना महंत का संसदीय कार्यकाल

■ संसद सत्र में मजबूत उपस्थिति व रेल, कोयला, प्रदूषण, सहित मूलभूत सुविधाओं पर मुखर रही

■ मेडिकल कॉलेज व ईएसआईसी हॉस्पिटल प्रारंभ कराने में रही अहम भूमिका

कोरबा। लोकसभा क्षेत्र की सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत के संसदीय कार्यकाल को 4 वर्ष पूरे हुए हैं। 23 मई 2019 को उन्होंने अपने संसदीय कार्यकाल की शुरूआत की। कोरबा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुन कर देश के सर्वोच्च सदन में भेजा। वे छत्तीसगढ़ से एकमात्र कांग्रेस की सांसद होने के बाद भी संसद में कोरबा संसदीय क्षेत्रवासियों सहित छत्तीसगढ़ प्रदेशवासियों की मुखर आवाज बनकर उभरीं। संसद की गतिविधियों से लेकर विभिन्न बैठकों और चर्चाओं में उन्होंने निरंतर अपनी सहभागिता दर्ज कराई है। निर्वाचित सांसदों में उनकी उपस्थिति 70 प्रतिशत दर्ज हुई है। उपस्थिति के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर औसतन 79 प्रतिशत एवं राज्य स्तर पर 89 प्रतिशत की उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। संसद के बजट सत्र, मानसून सत्र एवं शीतकालीन सत्र में भी उनकी उपस्थिति रही। वर्ष 2023 के बजट सत्र में उन्होंने 46 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज कराई और बजट सत्र में हिस्सा लिया साँसद ने माना है को कोरोना काल के सत्र में उनकी उपस्थिति नही रही । सांसद के द्वारा कोरबा से जुड़े रेल सुविधाओं के मामलों, केन्द्रीय विद्यालयों में सांसद कोटा बढ़ाने की मांग, कोयला खदानों से प्रभावित लोगों के सामाजिक सरोकार व क्षतिपूर्ति के मामले हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों पर पूर्ति, छत्तीसगढ़ राज्य में बढ़ते प्रदूषण और इसके समाधान के विषयों पर केन्द्र सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम, किसान फसल योजना का लाभ में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को भी जोडने का आग्रह के साथ-साथ शौचालयों का उपयोग की निगरानी जैसे विषय पर डिबेट में हिस्सा लिया गया। सांसद के संसद के सत्रों के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर तारांकित व अतारांकित प्रश्न लगाकर इसके जवाब मांगे गए। उपभोक्ताओं से जुड़े मामले, संस्कृति विधि एवं न्याय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, टेस्ट टाइल्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, पर्यावरण वन एवं क्लाइमेट चेंज, आयुष जनशक्ति, ऊर्जा नवीनीकरण एवं पुनः चक्रीकरण, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास, वित्त, शिक्षा, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कृषि एवं किसान कल्याण, महिला एवं बाल विकास, रेलवे, गृह मामलों, श्रम एवं रोजगार, ट्रायबल अफेयर्स, आवास एवं शहरी मामलों, इन्फारमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रानिक्स एंड इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी एवं योजना, वाणिज्य एवं उद्योग, रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवे, सोशल जस्टिस एवं इन्पावरमेंट, उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, माइंस, सिविल एविएशन, स्टील, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, कम्युनिकेशन जैसे मंत्रालयीन विभागों में उन्होंने सवाल किए। सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत ने कहा है कि कोरबा क्षेत्र की जनता का उन्हें असीम स्नेह व आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। क्षेत्र व क्षेत्रवासियों के विकास के लिए वे निरंतर संसद में आवाज उठाती रही हैं। खासकर कोरबावासियों के रेल सुविधाओं, एसईसीएल की विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावितों को अधिक से अधिक लाभ दिलाने के मामले में उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी बात संसद में रखी है।

छत्तीसगढ़
प्रमुख समाचार

गृहमंत्री साहू ने किया अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय बेरला का शुभारंभ

बेमेतरा। प्रदेश के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कल अनुविभाग बेरला में नवनिर्मित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम गृहमंत्री श्री साहू द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मूर्ति पर माल्यार्पण तथा पूजा अर्चना कर कार्यालय का उद्घाटन किया गया तथा नवीन अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय को क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी सौगात बताया साथ ही समस्त नागरिकों को नए कार्यालय खुलने पर हार्दिक बधाई भी प्रदान किए। इस अवसर पर विधायक बेमेतरा श्री आशीष कुमार छाबड़ा, कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला युगल किशोर उर्वशा, वरिष्ठ जनप्रतिनिधि बंशी पटेल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उद्घाटन के अवसर पर गत गुरुवार ग्राम कुसमी में गाज से प्रभावित होकर 21 बकरियों की मृत्यु हो जाने के कारण तहसील कार्यालय बेरला से सहायता राशि जारी की गई थी।

राइस मिल में लगी भीषण आग, बारदाने जलकर खाक

बलौदाबाजार। देर रात एक राइस मिल में भीषण आग लग गई, आग की चपेट में आकर दो ट्रक समेत बारदाने जलकर खाक हो गए। आग लगने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकलकर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। मामला राजा देवरी थाना क्षेत्र के चेचरापाली गांव की है जहां मनोज नायक की आनंद राइस मिल में देर रात करीब दो बजे शॉर्ट शर्किट की वजह से भीषण आग लग गई। आग की लपटें धीरे-धीरे बारदानों की तरफ बढ़ गई। देखते ही देखते आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों में वहां खड़े दो ट्रक भी चपेट में आए गए। थोड़ी देर में दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए। आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी लेकिन दूसरी अधिक होने के कारण उन्हें पहुंचने में दो घंटे लग गया और तब तक दोनों ट्रक तक बारदाना जलकर खाक हो चुका था। सुबह करीब 5 बजे दमकल की टीम पहुंची और 9 बजे आग पर काबू पाया जा सका।

माकड़ी ढाबा से मरकाटोला के बीच सड़क कार्य का शुभारंभ

कांकेर। संसदीय सचिव श्री शिशुपाल शोरी ने 8 करोड़ 98 लाख 69 हजार की लागत से माकड़ी ढाबा से फत्तेचंद मरकाटोला के बीच 11.80 किलोमीटर सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का माकड़ी चौक में शुभारंभ किया। यह सड़क कांकेर-भानुप्रतापपुर-संबलपुर के मध्य स्थित है। इस अवसर पर संसदीय सचिव श्री शोरी ने कहा कि सड़के किसी भी क्षेत्र या राज्य के विकास का आईना होती है। जहां सड़क नहीं वहां विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव से लेकर शहर तक सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य कर रही है। कांकेर विधानसभा के अधिकांश जगहों में सड़क के निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और इसका सीधा फायदा आम जनता को मिल रहा है। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य श्री नितिन पोटाई सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

मेरा गौठान मेरा अभिमान के तहत कटकोना स्थित गौठान मे कार्यक्रम का आयोजन

एमसीबी। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के निर्देशानुसार समस्त संगठनात्मक जिला एवं विधानसभा ईकाईयों को 22 मई 2023 से 07 जून 2023 तक प्रदेश के सभी गौठान मे मेरा गौठान, मेरा अभिमान (गौ सेवा पखवाड़ा) आयोजित करने निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य मे दिनांक 22/05/2023 को मनेंद्रगढ़ विधानसभ अंतर्गत खंडगवा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कटकोना के गौठान मे स्व सहायता समूह की दीदीओ का शाल श्रीफल से सम्मान कर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया तथा कांग्रेस सरकार मे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के बारे मे जानकारी दी गई। जिसमे प्रमुख रुप से गौठान समिति के सदस्य, महिला स्वसहायता समूह के सदस्य, सांसद प्रतिनिधि, जनपद पंचायत खंडगवा अशोक श्रीवास्तव,युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष हफीज मेमन, कटकोना सरपंच भुनेस्वरी मरकाम,जारोन्ध सरपंच प्रदीप सिंह, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मनोज शर्मा आदि उपस्थित थे।

कोरबा व कटघोरा वन मंडल में 1.10 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते संग्रहित

कोरबा। तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य अब अंतिम चरण की ओर है। कोरबा व कटघोरा वन मंडल में 1.41 लाख मानक बोरा पत्ता संग्रहित किए जाने का लक्ष्य है। 16 दिन के भीतर दोनों वन मंडल में 1.10 लाख मानक बोरा पत्ता संग्रहित कर लिया गया है। बीते वर्ष की तुलना में यह 36 हजार 120 मानक बोरा अधिक है। मौसम अनुकूल होने से पत्ता तोड़ाई का काम 728 में से 321 फड़ों में लगभग पूरा हो चुका है। पत्ते फड़ से गोदामों संग्रहित होने लगे हैं। अब हितग्राहियों को मजदूरी का इंतजार है। कोरोना काल में लगातार दो साल तक तेंदूपत्ता संग्रहण बाधित रहा। लाकडाउन के अलावा गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए जान के कारण संग्राहक परिवार जंगल तक नहीं पहुंच पाए थे। जारी वर्ष में तेंदूपत्ता संग्रहण हितग्राहियों के लिए वरदान साबित हो रहा। संग्रहण के लिए पर्याप्त समय मिलने से करीब आधे फड़ों में पत्तों की पूर्ण तोड़ाई कर ली गई है।

424 गौठानों में गोधन न्याय योजना के तहत की जा रही गोबर खरीदी

■ राजनांदगांव के फुलझर में मवेशियों हेतु कोटना में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही

राजनांदगांव। जिला राजनांदगांव अंतर्गत कुल 407 ग्राम पंचायतों में 424 गौठान स्वीकृत हैं। जिनमें से 414 ग्रामीण क्षेत्रों एवं 10 शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत हैं। जिसमें सभी गौठानों में राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत नियमित रूप से गोबर खरीदी की जा रही है। अब तक कुल 16004 गोबर विक्रेताओं से कुल 605296.66 क्विंटल गोबर का क्रय गौठानों में किया गया है। खरीदे गये गोबर से अब तक कुल 167469.44 क्विंटल जैविक खाद का उत्पादन किया जा चुका है तथा कुल 130047.18 क्विंटल खाद का विक्रय किया जा चुका है। खाद विक्रय से अब तक स्वसहायता समूहों को कुल 3 करोड़ 93 लाख रूपए से अधिक की लाभांश राशि का भुगतान भी किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान स्थिति में जिले के कुल 159 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं।

विगत दिनों विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा राजनांदगांव विकासखण्ड के फुलझर, पारीकला एवं ककरेल गौठान का भ्रमण किया गया एवं आपत्तियां जताते हुए भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किये गये है। फुलझर गौठान में पानी की उपलब्धता एवं बाउण्ड्री नहीं होने की बात कही गयी है। यद्यपि गौठान से लगे हुए स्कूल से रबर पाईपलाईन के माध्यम से मवेशियों हेतु कोटना में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है तथापि गौठान में आवश्यकतानुरूप पर्याप्त पानी उपलब्ध है। उक्त गौठान में चेन फेसिंग का कार्य स्वीकृत है एवं कार्य प्रगतिरत है। इसी प्रकार पारीकला गौठान में सरपंच को भुगतान शेष होना तथा गोबर खरीदी नहीं होना कहा गया है, जबकि स्वीकृत कार्य की राशि 8 लाख 89 हजार रूपए के विरूद्ध संबंधित कार्य एजेंसी को राशि 8 लाख 47 हजार रूपए का भुगतान जा चुका है तथा पारीकला गौठान में कुल 38 पंजीकृत गोबर विक्रेताओं से 372.31 क्विंटल गोबर की खरीदी की जा चुकी है। इसी तरह ककरेल गौठान में पानी एवं पैरा व चारा की अनुपलब्धता एवं गोबर की राशि भुगतान नहीं होने के संबंध में कहा गया है, जबकि इस गौठान में समीप के तालाब के माध्यम से रबर पाईप द्वारा मवेशियों हेतु पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है एवं मवेशियों हेतु ग्राम पंचायत द्वारा पैरा पंचायत क्षेत्र में संग्रहित किया गया है। साथ ही गत पखवाड़े में गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की राशि का भुगतान किया जा चुका है। जिला राजनांदगांव में कुल 407 गौठानों हेतु 3 चरणों में स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसके अंतर्गत तृतीय चरण के गौठानों में मूलभूत सुविधाओं का कार्य प्रगतिरत है। जिन्हें जल्द से जल्द से पूर्ण कराये जाने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया है।

युवा कांग्रेस ने शुरू किया मोर गौठान मोर अभियान कार्यक्रम

■ भाजपा के चलबो गौठान खोलबो पोल है नकली अभियान - पीयूष सोनी

दल्लीराजहरा। भाजपा के नकली अभियान चलबो गौठान खोलबो पोल के विरुद्ध युवा कांग्रेस का असली अभियान मोर गौठान मोर अभियान की शुरुआत डोंडी ब्लॉक के ग्राम सल्हाईटोला के आदर्श गौठान से की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक व महिला व बाल विकास मंत्री प्रतिनिधि पियूष सोनी युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकडे, ब्लाक अध्यक्ष कोमेश कोर्रम सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता ने बालोद जिले के सबसे उत्कृष्ट गौठान सलहाईटोला के सदस्यों से की चर्चा की इस दौरान सरपंच व महिला सदस्य प्रेमलता देवांगन सहित गोठान समिति के सदस्य उपस्थित थे। ज्ञात हो कीभाजपा के पाखंड को लोगो के बीच मे धराशायी करने के लिए आज़ डोंडी ब्लाक मे युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत बोकड़े ने मोर गौठान मोर जिम्मेदारी कार्यक्रम की शुरुआत की इस अभियान मे गौठान के सदस्यों का सम्मान और उनके द्वारा किया जा रहा कार्यों को समझा, गौठान से होने वाले आय पर महिलाओ की आय मे कितनी वृद्धि हुई उस पर आज़ संगोष्ठी की गयी,इसी परिचर्चा मे आज़ क्षेत्र के प्रदेश प्रतिनिधि पियूष सोनी,युवा कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत बोकड़े , ब्लॉक अध्यक्ष कॉमेश कोर्रम , जनपद सदस्य टीकम नेताम , हेमबती कुलदीप, यश राणा, कोमलेन्द्र चंद्राकर, समिति के सदस्य प्रेमबती देवांगन व कार्यक्रम के प्रभारी रविकांत देशमुख, शोएब खान, जागेश्वर ठाकुर, संदीप देवांगन, शाहरुख खान, पार्षद पलटन भुआर्य, भावेश यादव,सरपंच बूढ़ानसिंह उईके, नाथू राम, संजय भंडारी होरीलाल , कैलाश ठाकुर , सरजूराम बरसेल,ने इस चर्चा और सम्मान कार्यक्रम मे भाग लिया।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

2047 में भारत करेगा विश्व का नेतृत्व : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को सीमा सुरक्षा बल की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक प्रगति उसकी सुरक्षा से गहराई से जुड़ी हुई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) जैसे रक्षा बल भारत के समग्र विकास को संरक्षित करने का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस दौरान भारत के आर्थिक विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश इस समय तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। 2047 तक जब भारत आजादी के सौ साल पूरे करेगा तब वह ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। वे राजधानी दिल्ली में बीएसएफ के वार्षिक रुस्तमजी स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे। व्याख्यान में अपने संबोधन में धनखड़ ने कहा कि जो विकास पहले होना चाहिए था वह अब हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज आप देखते हैं कि हमारे पास किस तरह का बुनियादी ढांचा है, जिस तरह की तकनीकी भागीदारी हो रही है, जिस तरह के हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं और जिस तरह की सुविधाएं मानव संसाधन के लिए बनाई जा रही हैं। वह बेहतरीन हैं।

केजरीवाल ने उद्धव से अध्यादेश के खिलाफ मांगा समर्थन

मुंबई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मुंबई में शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान, केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) की लड़ाई में उद्धव का समर्थन मांगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, हम सब देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। मुझे लगता है कि हमें विपक्षी दल नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें (केंद्र को) विपक्षी और विरोधी बोलना चाहिए। क्योंकि वे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ हैं। उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, 'आप' के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा तथा दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी भी केजरीवाल के साथ थीं।

विपक्षी एकता में जुटे नीतीश ने त्यागी को दी बड़ी जिम्मेदारी

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की कवायद में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने जद (यू) के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी को पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त करके विपक्षी एकता के अभियान में लगे रहने के अपने इरादे को मजबूत किया है। केसी त्यागी पांच दशकों से राजनीति में हैं और वह देश के अधिकांश समाजवादी नेताओं के अधीन काम करने का अनुभव रखते हैं। माना जा रहा है कि त्यागी 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने में सहायक हो सकते हैं। मैंने नीतीश से मेरी सांगठनिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने का अनुरोध किया था, जिसे दो महीने पहले स्वीकार कर लिया गया था। इसके साथ ही त्यागी ने कहा कि विपक्षी दलों के बीच अंतर्विरोधों को समाप्त करने और अगले आम चुनावों के लिए एक साथ आने के उनके वर्तमान प्रयास को देखते हुए बिहार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी के नए पासपोर्ट बनवाने की अर्जी का किया विरोध

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी को नया साधारण पासपोर्ट जारी करने की अनुमति मांगने वाले राहुल गांधी के आवेदन का विरोध करते हुए जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने तर्क दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ मामले अदालत के समक्ष लंबित हैं और उन्हें यात्रा करने की अनुमति देने से नेशनल हेराल्ड मामले में चल रही जांच प्रभावित होगी। हालांकि, गांधी की ओर से पेश अधिवक्ता तरन्नुम चीमा ने कहा कि अदालत ने उन पर कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं लगाया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और 2015 में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिलने के दौरान राहुल गांधी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। अदालत ने स्वामी को एक लिखित जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को 26 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

आजम खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था, बुधवार को उसी मामले में आजम खान को बरी कर दिया गया। हेट स्पीच मामले में आजम खान को 3 साल की सजा हुई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। 27 अक्टूबर 2022 को भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें 3 साल की सजा सुनाई थी। आजम खान को 3 साल की सजा होने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। इतना ही नहीं, आजम खान के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था। बाद में आजम खान ने एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को लेकर याचिका दाखिल की थी। बहस पूरा होने के बाद इस पर फैसला आया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान की 3 साल की सजा को आज खारिज कर दिया है। इसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया।

नए संसद भवन को लेकर राजनीति, संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है

राष्ट्रपति से उद्घाटन न करवाना सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान : राहुल

नईदिल्ली। देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भवन का उद्घाटन करेंगे लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और मनीष तिवारी द्वारा अपने सुझाव के समर्थन में संविधान के कई लेखों का हवाला देने के घंटों बाद आई कि भारत के राष्ट्रपति को पीएम के बजाय भवन का उद्घाटन करना चाहिए।

वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अपनी राय प्रकट की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना - यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती है। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं!

नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्ष ने जारी किया साझा बयान

बुधवार को 19 विपक्षी दलों ने इसका बहिष्कार करने के लिए एक संयुक्त बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जब संसद से लोकतंत्र की आत्मा को ही छीन लिया गया है, तो हमें एक नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा, नए संसद भवन का उद्घाटन एक यादगार अवसर है। हमारे इस भरोसे के बावजूद कि यह सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा है और जिस निरंकुश तरीके से नई संसद का निर्माण किया गया था, उसके प्रति हमारी अस्वीकृति के बावजूद हम मतभेदों को दूर करने के लिए इस अवसर पर शामिल होने के लिए खुले थे। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन खुद ही करने का प्रधानमंत्री मोदी का फैसला न केवल उनका अपमान है, बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है।

इसमें आगे कहा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाएगा। राष्ट्रपति न केवल भारत में राष्ट्र प्रमुख है, बल्कि संसद के एक अभिन्न अंग भी है। बयान में आगे कहा गया, संसद उनके (राष्ट्रपति) बिना काम नहीं कर सकती। यह अमर्यादित कृत्य संसद के उच्च पद का अपमान करता है, और संविधान की मूल भावना का उल्लंघन करता है। यह समावेश की भावना को कमजोर करता है।

साझा बयान में आगे कहा गया है कि अलोकतांत्रिक कृत्य प्रधानमंत्री के लिए नए नहीं हैं, जिन्होंने संसद को लगातार खोखला किया है। भारत के लोगों के मुद्दों को उठाने पर संसद के विपक्षी सदस्यों को अयोग्य घोषित, निलंबित और मौन कर दिया गया है। सांसदों की बेंच ने संसद को बाधित कर दिया। तीन कृषि कानूनों सहित कई विवादास्पद कानूनों को लगभग बिना किसी बहस के पारित किया गया, और संसद की समितियों को आंशिक रूप से निष्क्रिय कर दिया गया। नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों के साथ कोई परामर्श नहीं किया गया है, जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है।

जिन पार्टियों ने यह साझा बयान जारी किया है उनमें कांग्रेस, द्रमुक, आप, शिवसेना (यूबीटी), समाजवादी पार्टी, भाकपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस (मणि), विदुथलाई चिरुथैगल काची, राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल (यूनाइटेड), भाकपा (मार्क्सवादी), राष्ट्रीय जनता दल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल), नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके शामिल हैं।

नई संसद में रखा जाएगा तमिलनाडु का 'सेंगोल' : अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि नई संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत करेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रतीक सेंगोल (राजदंड) के पुनः परिचय की भी घोषणा की क्योंकि यह अंग्रेजों से भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। शाह ने कहा, इस सेंगोल का बहुत बड़ा महत्व है...14 अगस्त 1947 की रात लगभग 10.45 बजे पंडित नेहरू ने तमिलनाडु से इस सेंगोल को प्राप्त किया और कई वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में उन्होंने इसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया...यह एक बदलाव का संकेत है अंग्रेजों से इस देश के लोगों को सत्ता का। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय, विशेषकर तमिल संस्कृति में सेंगोल का बहुत महत्व है। अमित शाह ने कहा, सेंगोल चोल राजवंश के समय से ही महत्वपूर्ण रहा है...इस सेंगोल को नई संसद में रखा जाएगा...पीएम मोदी इस सेंगोल को स्वीकार करेंगे और इसे स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। शाह ने कहा कि पीएम मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले तमिलनाडु से सेनगोल प्राप्त करेंगे और वह इसे नए संसद भवन के अंदर रखेंगे।

विपक्ष के विरोध के बीच दो दल नए संसद भवन के उद्घाटन में होंगे शामिल

नईदिल्ली। विपक्षी दलों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इन सब के बीच मोदी सरकार के लिए इन दो दलों ने राहत भरी खबर दी है। तेलुगु देशम पार्टी 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होगी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इसकी पुष्टि की है। वहीं, वाईएसआरसीपी (युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी) 28 मई को दिल्ली में नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होगी, पार्टी के सांसद विजयसाई रेड्डी ने एएनआई से इसकी पुष्टि की।

सूत्रों ने बताया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने पर अंतिम निर्णय शनिवार, 27 मई को बीजद (बीजू जनता दल) प्रमुख और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किए जाने पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहिष्कार कर एक बिना-बात का मुद्दा बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे अपने इस निर्णय पर फिर से विचार करने की अपील करूंगा और कृपया कर इसमें शामिल हों। स्पीकर संसद का संरक्षक होता है और स्पीकर ने प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह राष्ट्रपति और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करता है... आप लोकतांत्रिक सिद्धांतों और प्रोटोकॉल को कमजोर कर रहे हैं इसलिए कांग्रेस पार्टी ने सभी समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से बात की और वह इस कार्यक्रम को बहिष्कार करने के लिए तैयार हुए... अगर राष्ट्रपति नए संसद भवन का उद्घाटन कर रही हैं तो आप (प्रधानमंत्री) एक मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रह सकते हैं लेकिन आप उनकी (राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति) मौजूदगी नहीं चाहते।

विपक्ष के बहिष्कार पर बोले एकनाथ शिंदे मोदी के नेतृत्व में टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि देश की उन्नति दुनिया के सामने है। दुनिया भारत का सम्मान कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ, उतना विकास पिछले 8-9 साल में हुआ है। जनता सब जानती है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में टूट जाएंगे। शिअद नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के लिए गर्व की बात है, इसलिए हमने फैसला किया है कि शिरोमणि अकाली दल 28 मई को उद्घाटन समारोह में शामिल होगा। हम विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत नहीं हैं।

अपना चेहरा बचाने के लिए वे बहिष्कार का नाटक कर रहे : हिमंता बिस्वा सरमा

असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने बयान में कहा कि बहिष्कार स्पष्ट है। उन्होंने संसद भवन के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि निर्माण इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। इसलिए, विपक्ष के लिए सब कुछ बाउंसर की तरह हुआ है। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि बस अपना चेहरा बचाने के लिए वे बहिष्कार का नाटक कर रहे हैं। सरमा ने आगे कहा कि वीर सावरकर से जुड़े दिन संसद भवन खुलेगा। यह उनके लिए समारोह का विरोध या बहिष्कार करने का एक और कारण हो सकता है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये मुद्दा विहीन लोग हैं जो देश के संसद भवन को चुनाव मैदान की तरह देख रहे हैं। भारत की संसद इस लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करना किसी भी राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विपक्ष की तरफ से एक निराधार बहस उठाने का काम किया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इनके शासन काल में इनके प्रधानमंत्रियों के द्वारा ऐसे उद्घाटन नहीं हुए।

खेल
प्रमुख समाचार

आईपीएल फाइनल से बाहर हो सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी

चेन्नई। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने मंगलवार को चेपॉक स्टेडियम में गुजरात टाइटंस को 15 रनों से हराकर आईपीएल 2023 के फाइनल में पहुंच गयी है। सीएसके रिकॉर्ड 10वीं बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचने वाली टीम बनी है। हालांकि अब खिताबी भिड़ंत के पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, आईपीएल के फाइनल से फैंस के चहेते और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बाहर हो सकते हैं। धोनी के आईपीएल फाइनल से बाहर होने के कारण गुजरात के खिलाफ मैच में घटी एक घटना है। गुजरात के खिलाफ मैच के दौरान चेन्नई के लिए 16वां ओवर सीएसके के स्टार तेज गेंदबाज मथीसा पाथिराना लेकर आए थे। हालांकि अंपायर ने उन्हें गेंदबाजी करने से रोक दिया था। दरअसल, पाथिराना इससे पहले बीच मैच के दौरान 9 मिनट के लिए ग्राउंड से बाहर गए थे। वहीं नियम के अनुसार वह तभी गेंदबाजी कर सकते थे जब वह इतना ही वक्त मैदान पर बीता चुके हो पर ऐसा नहीं हुआ था और कप्तान धोनी ने उन्हें गेंदबाजी के लिए बुलाया पर अंपायर ने उन्हें रोक दिया। अंपायर के रोकने के बाद धोनी और मैदानी अंपायर्स में 5 मिनट तक बहस भी हुई। इस बहस के कारण चेन्नई को अपने पूरे ओवर को खत्म करने में 4 मिनट की देर हुई। इस देर के बाद अब माना जा रहा है कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर फाइन या उन्हें फाइनल से बैन भी किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

इस पूरी घटना पर कमेंट्री कर रहे भारत के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गावस्कर ने कहा कि 'आपको अंपायर के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। कई बार अंपायर से अधिक प्रश्न वाल मुकाबले में गलती हो जाती है पर हमें उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए'।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 208 अंक लुढ़का, निफ्टी भी 18,300 के नीचे आई

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में तीन दिन से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। आज के कारोबार में सेंसेक्स 208 अंक टूटा। वहीं, निफ्टी में भी 63 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कारोबार के अंत में निफ्टी 18,285.40 पर बंद हुआ। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 208.01 अंक यानी 0.34 फीसदी मजबूत 61,773.78 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 62,154.14 की ऊंचाई तक गया और नीचे में 61,708.10 तक आया। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 62.60 अंक यानी 0.34 फीसदी चढ़ा। निफ्टी दिन के अंत में 18,285.40 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान निफ्टी 18,392.60 की उंचाई तक गया और नीचे में 18,262.95 तक आया।

महंगाई से जंग जारी, ढील नहीं दे सकते : गवर्नर

नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को एक कार्यक्रम में कहा, हालांकि महंगाई हाल के दिनों में कम हुई है, लेकिन इसके खिलाफ भारत की जंग अभी भी जारी है और आत्मसंतोष के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा ब्याज दर में वृद्धि को रोकना उनके हाथ में नहीं है, यह उस समय की जमीनी स्थिति पर निर्भर करता है। उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक सत्र 2023 में कहा, 'महंगाई से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हमें सतर्क रहना होगा और आत्मसंतोष का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि रिटेल महंगाई के अगले आंकड़े में महंगाई दर के घटकर 4.7 फीसदी से नीचे आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन और इसकी बैंकिंग प्रणाली के लचीलेपन के दम पर, 2022-23 के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7 फीसदी से अधिक हो सकती है।

उबर ने ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की ओर बदलाव के लिए कई ईवी कंपनियों से मिलाया हाथ

नईदिल्ली। ऐप आधारित कैब सेवाएं देने वाली कंपनी उबर ने भारत में विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और अन्य इकाइयों के साथ हाथ मिलाने की घोषणा की है। उबर ने बुधवार को कहा कि वह अपने भागीदारों के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की ओर बदलाव में मदद करना चाहता है। कंपनी ने कहा कि उसने अगले दो साल में भारत में उबर मंच पर 25,000 इलेक्ट्रिक कारों को तैनात करने के लिए ईवी फ्लीट भागीदार लिथियम अर्बन टेक्नोलॉजीज, एवरेस्ट फ्लीट प्राइवेट लिमिटेड और मूव के साथ अपनी भागीदारी का विस्तार किया है। इसके अलावा उबर ने 2024 तक दिल्ली में 10,000 ईवी दोपहिया वाहनों के लिए जिप इलेक्ट्रिक के साथ साझेदारी की है। कंपनी ने ईवी फंडिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपये निकालने को सिडबी से भी हाथ मिलाया है।

महिंद्रा थार को टक्कर देने आ रही मारुति की एसयूवी

नईदिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया को उम्मीद है कि उसकी नई पेशकश जिम्नी से न केवल कंपनी की बिक्री बढ़ेगी, बल्कि तेजी से बढ़ते स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन सेगमेंट में उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। कंपनी का इरादा इस सेगमेंट में टॉप खिलाड़ी बनने का है। कंपनी अगले महीने देश में इस मॉडल को उतारने की तैयारी कर रही है। कंपनी का मानना है कि ब्रेजा, फ्रोंक्स और ग्रैंड विटारा जैसे अन्य मॉडलों के साथ जिम्नी एसयूवी सेगमेंट में उसकी स्थिति को मजबूत करने में भूमिका निभाएगी। कंपनी का चालू वित्त वर्ष में एसयूवी सेगमेंट में शीर्ष स्थान हासिल करने का लक्ष्य है। मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (बिक्री एवं विपणन) शशांक श्रीवास्तव ने बातचीत में कहा कि जिम्नी का कंपनी के समग्र ब्रांड मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वित्तीय समावेशन के जरिये मोदी ने गरीब वर्ग का कर दिया कायाकल्प

प्रहलाद सबनानी

15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जनधन योजना' की घोषणा की थी और बिना समय गंवाए 28 अगस्त 2014 से यह योजना पूरे देश में प्रारम्भ कर दी गई थी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय ने देश में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की दशा एवं दिशा बदल दी थी। इस योजना का दूसरा संस्करण अधिक लाभों को जोड़ते हुए वर्ष 2018 में प्रारम्भ किया गया था। इस दूसरे संस्करण में प्रत्येक परिवार के स्थान पर प्रत्येक उस व्यक्ति को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने की घोषणा की गई थी जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित थे। इस पहल का नतीजा आज हम सभी के सामने है कि देश आर्थिक विकास के रास्ते पर इतना आगे बढ़ चुका है कि पूरी दुनिया भारत को वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर एक चमकता हुआ सितारा मान रही है।

किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश के नागरिकों के वित्तीय सेवाओं से जुड़े होने पर भी निर्भर करता है। जितनी अधिक जनसंख्या वित्तीय सेवाओं से जुड़ी होगी, उस देश की आर्थिक स्थिति उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन, आजादी के बाद से भारत में आबादी का एक बहुत बड़ा भाग और समाज का निम्न आय वर्ग बड़ी संख्या में वित्तीय सेवाओं से वंचित रहा है। जबकि गरीबी को कम करने में वित्तीय समावेशन एक प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। वर्ष 2014 में देश के करोड़ों नागरिकों के पास मोबाइल फोन तो था परंतु उनका बैंक में बचत खाता नहीं था। नागरिक बैंक में जाने से डरते थे। नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक ऐसी योजना की आवश्यकता थी जिससे सभी नागरिक इससे होने वाले लाभ अर्जित कर सकें एवं भारत के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। अतः नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। इससे हाल के दिनों में सामान्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में एवं विशेष रूप से बैंकिंग सेवाओं में बहुत ही तेज गति से प्रगति हुई है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से आम नागरिकों के बैंकों में बचत खाते खोले गए, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, धन के प्रेषण की सुविधा, बीमा तथा पेंशन सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अंतर्गत जमाराशि पर ब्याज मिलता है, हालांकि बचत खाते में कोई न्यूनतम राशि रखना आवश्यक नहीं है। एक लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। साथ ही, इस योजना के माध्यम से दो लाख रुपए का जीवन बीमा उस लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों पर मिलता है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से दिए जाने वाले लाभ के अंतरण की सुविधा भी इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होती है। भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश के हर गरीब नागरिक को वित्तीय मुख्य धारा से जोड़ा है। समाज के अंतिम छोर पर बैठे गरीबतम व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिला है। आजादी के लगभग 70 वर्षों के बाद भी भारत के 50 प्रतिशत नागरिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ अर्थात बैंकों से नहीं जुड़े थे। इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 तक 48.65 करोड़ बचत खाते विभिन्न बैंकों में खोले जा चुके हैं। साथ ही, इन खाताधारकों द्वारा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि इन जमा खातों में जमा की गई है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाताधारकों को प्रदान की जाने वाली अन्य सुविधाओं का लाभ भी भारी मात्रा में नागरिकों ने उठाया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 15.99 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 49 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का जीवन बीमा केवल 436 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 33.78 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं, इनमें 48 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा केवल 20 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध कराया जाता है। अटल पेंशन योजना से 5.20 करोड़ नागरिक जुड़ गए हैं। मुद्रा योजना के अंतर्गत 40.83 करोड़ नागरिकों को ऋण प्रदान किया गया है।

क्रमशः ...

कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत ही सबसे बड़ी कमजोरी

आदिति फडणीस

कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरमैया कांग्रेस के सबसे उपयुक्त और वास्तव में कहीं अ?धिक तर्कसंगत उम्मीदवार थे। आंकड़ों से अन्य तमाम बातों के अलावा दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के नीलांजन सरकार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का स्ट्राइक रेट (जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी उसके मुकाबले जीती गई सीटें) 2018 में 55 से घटकर 2023 में 25 रह गया। जबकि कांग्रेस के लिए समर्थन 35 से बढ़कर 63 हो गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कर्नाटक के शहरी इलाकों में भाजपा की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में उसका समर्थन कम हुआ है। दूसरा निष्कर्ष दक्षिण कर्नाटक से संबंधित है जो कर्नाटक में वोक्कालिगा-बहुल कपास और गन्ना पट्टी है। इस क्षेत्र में जनता दल (सेक्युलर) यानी जेडी (एस) की मजबूत उपस्थिति हुआ करती थी। सिद्धरमैया भी इसी क्षेत्र से आते हैं। यहां कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2018 में 29 से बढ़कर इस बार 62 हो गया। जबकि भाजपा 21 से फिसलकर 10 पर आ गई। मगर दोनों पार्टियां जेडी(एस) के वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहीं। इस क्षेत्र में जेडी(एस) का स्ट्राइक रेट इस बार घटकर 25 रह गया जो 2018 में 46 था। यह पूरी कहानी नहीं है। सिद्धरमैया ने शहरी कर्नाटक के लिए अपनी वाकपटुता एवं जबरदस्त उपेक्षा के कारण ग्रामीण कर्नाटक में भाजपा को मात देने की पटकथा तैयार कर दी थी। ऐसा उन्होंने अपने शुरुआती दिनों के मजबूत किसान लॉबियों के संरक्षण में किया। इसमें कर्नाटक राज्य रैयत संघ के एमडी नंजुंदास्वामी जैसे कद्दावर नेता थे। कांग्रेस भले ही इसे स्वीकार न करे लेकिन उसे इसी का फायदा मिला है। लेकिन यदि सिद्धरमैया की शहरी विरोधी पूर्वग्रह पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह कांग्रेस की नई सरकार के लिए सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकता है। अपने पूर्व नेता एचडी देवेगौड़ा के साथ सिद्धरमैया के संबंध और वोक्कालिगा समुदाय के बारे में उनकी तीखी आलोचना जगजाहिर है। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अंतिम कार्यकाल (2013-2018) में प्रशासन के लिहाज से सिद्धरमैया का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा और उन्होंने सराहनीय राजकोषीय संयम दिखाया था। उन्होंने सामाजिक कल्याण की बड़ी परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। खाद्य सुरक्षा, पोषण और महिला केंद्रित उनकी योजनाएं काफी सफल रही थीं। मगर कर्नाटक में शहरी विकास पर आधारित निवेश आकर्षित के मोर्चे पर सिद्धरमैया का कोई दृष्टिकोण नहीं दिखा था। उनकी नीतियां काफी हद तक उनके राजनीतिक इतिहास और धारणाओं से उपजी थीं। वह 2005 में जेडी(एस) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। देवेगौड़ा को इस स्वाभिमानी राजनेता और शानदार वक्ता पर काफी गर्व था। मगर उन्होंने जेडी(एस) सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए अपने बेटे को तरजीह देते हुए सिद्धरमैया को उपमुख्यमंत्री बनाया। इस प्रकार उन्हें स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया गया था। साल 2013 में भी सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय काफी लंबा खिंच गया था और उसके लिए व्यापक विचार-विमर्श किया गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने विधायकों से बात की और इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष की राय जानने के लिए अहमद पटेल को फोन किया था। अधिकतर विधायक सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे लेकिन एंटनी ने पटेल को बताया कि विधायकों का एक बड़ा तबका आशंकित भी हैं और उनका कहना है कि किसी एक समुदाय की कीमत पर दूसरे को संतुष्ट नहीं किया जाना चाहिए।

नये भारत का प्रतीक है नया संसद भवन

सिद्धार्थ शंकर गौतम

28 मई, 2023 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नए संसद भवन का विधिवत उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों करवाने का मुद्दा उठाकर इसे राजनीति से जोड़ दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि भाजपा सिर्फ दिखावे के लिए दलित और आदिवासी का नाम लेती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा कि अगर राष्ट्रपति भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों होता तो अच्छा होता क्योंकि वो पक्ष विपक्ष सहित हर नागरिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक आरोप लगाया है कि संसद के उद्घाटन में राष्ट्रपति को बुलाया तक नहीं गया है।

असल में 29 मई, 2023 से मोदी सरकार के 9वें वर्ष का प्रारंभ होगा जो अगले एक वर्ष तक 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट करेगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत हो रहे अनेक निर्माण में नया संसद भवन भी शामिल है। किन्तु जैसा कि राजनीति में होता है, सत्ता पक्ष के हर कार्य का विरोध करो, ठीक ऐसा ही नए संसद भवन के निर्माण में भी विपक्ष द्वारा विरोध का झंडा बुलंद किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर विभिन्न मंत्रालयों तक इसे रोकने के प्रयास हुए हैं। कभी पर्यावरण के नाम पर तो कभी अपव्यय के नाम पर, विपक्ष ने प्रारंभ से ही इसे मुद्दा बनाते हुए इसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का निजी राजभवन तक बता दिया।

अब जबकि इसके उद्घाटन की संभावित तारीख आ गई है तो अब विरोध उद्घाटन करने और सावरकर जयंती पर आ गया है। किसी भी राष्ट्र की धरोहर उसकी संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला, वास्तुकला होती है। आखिर कोई राष्ट्र औपनिवेशिक विरासत को क्यों सहेज कर रखे जबकि वह स्वयं सांस्कृतिक रूप से विश्वगुरु रहा हो। जैसे राजपथ कर्तव्य पथ होकर लोकतंत्र को सम्मानित कर गया वैसे ही नया संसद भवन विश्व में भारत के संकल्प और लक्ष्य को प्रदर्शित करेगा। इसके बनने पर राजनीति होना स्वयं पर अविश्वास होने जैसा है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नए संसद भवन को 150 वर्षों तक की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से बनाया गया है। दरअसल, वर्तमान संसद भवन औपनिवेशिक युग का निर्माण है जो 1921 से प्रारंभ होकर 1927 में बना। लगभग 100 साल पुराना भवन भले ही हेरिटेज ग्रेड-1 भवन हो किन्तु स्थान की कमी इसमें हमेशा से आती रही है। यही कारण है कि 1956 में इसमें दो मंजिलों को जोड़ा गया। वर्तमान में इसके सेंट्रल हॉल में 440 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है और जब संसद के संयुक्त सत्र होते हैं तो सीटों की समस्या बढ़ जाती है। इसके अलावा आवाजाही के सीमित द्वार होने के कारण संसद की सुरक्षा हमेशा दांव पर लगी होती है। 13 दिसंबर, 2001 को भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले को कौन भूल सकता है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी और लोकतंत्र का मंदिर गोलियों की बौछार से छलनी हो गया था। 2006 में देश की 2,500 वर्ष की समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत को दिखाने के लिए इसी भवन में संसद संग्रहालय जोड़ा गया जिसमें आगंतुकों की संख्या कई गुना बढ़ गई है और अब यह भी छोटा लगने लगा है। इसके अलावा नए संसद भवन का निर्माण समय की मांग भी है। वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर किए गए परिसीमन के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या 545 है किन्तु 2026 के बाद इसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है क्योंकि सीटों की कुल संख्या पर रोक केवल 2026 तक है। यदि ऐसा होता है तो जनसंख्या अनुपात के आधार पर देश में लगभग 800 संसदीय क्षेत्र होंगे जिससे सांसदों की संख्या भी उतनी ही होगी। ऐसे में पुराना संसद भवन अपने आप अनुपयोगी हो जाएगा क्योंकि इतने सांसदों के बैठने का प्रावधान उसमें संभव नहीं है।

पुराने संसद भवन की तुलना में नए संसद भवन की कुल बैठक क्षमता 150 प्रतिशत से अधिक है। नए संसद भवन में सेंट्रल हाल नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी मयूर की थीम पर 3015 वर्ग मीटर एरिया में बने लोकसभा चैंबर में 543 सीटों के स्थान पर 888 सीटें हैं। जबकि कमल के फूल की थीम पर राज्यसभा चैंबर 3220 वर्ग मीटर एरिया में बना है जिसमें 245 के स्थान पर 384 सीटें हैं। नए संसद भवन परिसर में कुल मिलाकर 120 कार्यालय हैं जिसमें विभिन्न कमेटी कक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के कार्यालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय आदि प्रमुख हैं। पुराने संसद भवन के ठीक सामने बने नये संसद भवन में सांसदों के लिए पुस्तकालय, बैठक कक्ष, भोजन कक्ष इत्यादि भी हैं। यदि संसद का संयुक्त सत्र होता है तो लोकसभा का विस्तार करके वहां एक साथ 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की जा सकेगी। लोकसभा और राज्यसभा के कक्ष उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो-वीडियो उपकरणों से लैस हैं। साथ ही, हर डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से सुसज्जित है। सांसदों के कार्यालय भी आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस हैं। आधुनिक तकनीक की पार्किंग सुविधा इसकी खास पहचान है। नए संसद भवन की 4 मंजिला इमारत में 6 रास्तों से प्रवेश होगा जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए अलग रास्ता, लोकसभा अध्यक्ष के लिए अलग, राज्यसभा सभापति के लिए अलग, सांसदों के प्रवेश के लिए अलग तथा आम जनता के लिए अलग होगा। इससे सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होगी। पर्यावरण के अनुकूल निर्मित नए संसद भवन से ऊर्जा का अपव्यय भी रोका जा सकेगा। त्रिभुजाकार आकार में बन रहा नया संसद भवन भूकंपरोधी सिस्टम के अनुसार सुरक्षा पुख्ता करने वाला है। संसद भवन की नई इमारत में भव्य संविधान कक्ष में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दर्शाया जाएगा। साथ ही, यहां भारत के संविधान की मूल प्रति भी रखी जाएगी। नए संसद भवन के वास्तुकार 61 वर्षीय बिमल पटेल और उनकी अहमदाबाद स्थित कंपनी एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तमाम विरोधों और झंझावातों से पार पाते हुए इसका जो स्वरूप निखारा है वह भारतीयता की अनभूति कराता है। पद्मश्री से सम्मानित बिमल पटेल का नरेंद्र मोदी के साथ दो दशकों से अधिक का साथ है इसलिए विपक्ष ने उन्हें मोदी का वास्तुकार टैग भी दिया है। हालांकि इन सबसे विचलित न होते हुए बिमल पटेल और उनकी टीम ने कोरोना महामारी के कारण अवरोधित कार्य को भी समय से पूरा किया जिससे विपक्षी भी उनके काम के क़ायल हो चुके हैं। वर्तमान में बिमल पटेल सेंटर फॉर एन्वायरनमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं तथा एचसीपी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नेतृत्व करते हैं जो आर्किटेक्चर, प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फर्म है।

कृपया इनसे सीखें
यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला ?

बिहार के दशरथ माँझी की तरह ही हैं नवांशहर के 45 वर्षीय सुरिंदर सिंह। भले ही उन्होंने पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता न बनाया हो, लेकिन कोरोना काल में अकेले ही क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे ईंटों व पत्थरों से भरकर लोगों की राह जरूर आसान कर दी है। इलाके की सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता थी। सड़कों में जगह-जगह गड्ढे पड़ गए थे। यूं तो हर साल स्थानीय निकाय और लोक निर्माण विभाग बरसात से पहले सड़कों की मरम्मत करवा देते हैं, लेकिन कोरोना संकट के कारण इन विभागों से मरम्मत की उम्मीदें धुंधली पड़ने लगीं। दूसरे लोगों की तरह इस पर सिर्फ चिंता जाहिर करने के बजाय भारटा कलाँ गाँव के सुरिंदर सिंह ने सड़कों की हालत सुधारने में जुट गए।

सुरिंदर सिंह राहों में बैग, अटैची व सूटकेस आदि बनाने व उनकी मरम्मत का काम करते हैं। उनके पास एक पुरानी मारुति कार है। कार के पीछे जोड़ने के लिए उन्होंने जुगाड़ से एक छोटी ट्रॉली बनवा रखी है। इस ट्रॉली में वह आसपास से थोड़ा बहुत सामान लाते रहते हैं। कार और ट्रॉली के साथ वह कर्फ़्यू में सड़कों की हालत सुधारने निकल पड़े। उन्होंने भट्ठों से टूटी ईंटें लाकर सड़कों के गड्ढे भरना शुरु कर दिया। रोज सड़क के किसी एक हिस्से को चिन्हित कर उसे भरने लगे। क्षेत्र के आसपास की कई किलोमीटर लंबी सड़कों के सारे गड्ढे उन्होंने दो महीने में भर दिए हैं। सुरिंदर ने राहों-फिल्लौर रोड स्थित झुग्गी झोपड़ी के पास, सैनी अस्पताल के आगे, गुरु नानकपुरा कलाँ से भारटा खुर्द तथा गाँव कंग रोड, राहों-फिल्लौर-माछीवाड़ा टी-प्वाइंट चौक पर सड़क के गड्ढों को ईंटों व पत्थरों से भरकर ठीक किया। सुरिंदर सिंह कहते हैं कि कर्फ़्यू में सभी ने जरूरतमंद लोगों की अपने-अपने तरीके से मदद की। किसी ने राशन दिया तो किसी ने सैनिटाइजर और मास्क बाँटे।

आज की महत्वपूर्ण घटनाएं

2003 चिली ने पहली बार विश्व कप टेनिस ख़िताब जीता।
2006 नासा ने जीओईएसएन नामक मौसम उपग्रह अंतरिक्ष में रवाना किया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पोत आधारित इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
2007 श्रीलंका की सरकार ने तमिल शरणार्थियों की नागरिकता पर सैद्धांतिक अनुमति दी।
2008 अमेरिकी स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजा गया फिनिक्श रोवर मंगल ग्रह के सतह पर उतरा।
2011 अमेरिका के मशहूर ओपरा विफ्रे शो 25 साल बाद बंद किया गया। इस हिट अमेरिकी शो की एंकर ओपरा विफ्रे थी।
2012 स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के साथ मिलने वाला पहला व्यावसायिक अंतरिक्ष यान बन गया।
2013 जापान के 80 वर्षीय युईशिरो मिउरा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति बने।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

अक्ष्युपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

तो उसका भी उसी प्रकार परित्याग कर देता है, जैसे साँप अपनी केंचुल को छोड़ देता है। इस प्रकार का सद्ज्ञान सम्पन्न साधक शास्त्र, गुरु और सत्पुरुषों के सेवा-सहयोग द्वारा रहस्यपूर्ण गूढ़ज्ञान को भी प्रयत्नपूर्वक स्वाभाविक रूप में हस्तगत कर लेता है। इसके पश्चात् वह योग की असंसर्गनाम्नी तीसरी भूमिका में प्रवेश करता है ठीक उसी प्रकार, जैसे कोई सुन्दर मनुष्य साफ-सुधरे फूलों के बिछोने पर अवस्थित होता है।

शास्त्र जैसा अभिमत व्यक्त करते हैं, उसमें अपनी स्थिर मति को संयुक्त करके, तपस्वियों के आश्रम में वास करता हुआ अध्यात्म शास्त्र की चर्चा करते हुए (कष्टकर) पाषाण-शय्या पर आरूढ़ होते हुए ही वह सम्पूर्ण आयु बिता देता है। वह नीति पुरुष चित्त को शान्ति पहुँचाने वाले अधिक शोभाप्रद वन भूमि के विहार द्वारा विषयोपभोग से विरत होकर स्वाभाविक रूप में उपलब्ध सुख-साधनों को भोगता हुआ अपना जीवनयापन करता है। सद्ग्रन्थों के अभ्यास और पुण्य कर्मों के किये जाने से प्राणी की वास्तविक पर्यवेक्षण दृष्टि पवित्र होती है। इस तृतीय भूमिका को प्राप्त करके साधक स्वयमेव ज्ञानवान् होकर इस स्थिति का अनुभव करता है। असंसर्ग-सामान्य और श्रेष्ठ भेद से दो तरह का है। (उनके इस प्रकार के भेदों पर अब प्रकाश डालते हैं) मैं न तो कर्त्ता, न भोक्ता, न बाध्य और न बाधक ही हूँ इस प्रकार से विषयोपभोग में आसक्ति से रहित होने की भावना ही सामान्य असंसर्ग कहलाती है। सब कुछ पूर्वजन्म कृत कर्मों का प्रतिफल है या सब कुछ परमात्मा के अधीन है - ऐसी मान्यता रखना, सुख हो या दुःख इसमें मेरे किये गये कार्यों का अस्तित्व ही क्या है? भोगसाधनों का अतिसंग्रह महारोगरूप है और समस्त वैभव परम आपत्तियों के स्वरूप हैं। सभी संयोगों की अन्तिम परिणति वियोग के रूप में है। मानसिक चिन्ताएँ अज्ञानग्रस्तों के लिए व्याधिरूप हैं। सभी क्षणभंगुर पदार्थ अनित्य हैं, सभी को काल कराल अपना ग्रास बनाने में संलग्न है। (शास्त्रवचनों को जान लेने से उत्पन्न) अनास्था से मन में उनके अभाव की भावना को पैदा करता है, यह सामान्य असंसर्ग कहलाता है।

क्रमशः ...

आजाद हिंद सेना के संस्थापक थे रास बिहारी बोस

बाल मुकुन्द ओझा

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में रासबिहारी बोस का नाम आदर पूर्वक लिया जाता है। रासबिहारी बोस भारत के एक महान क्रान्तिकारी नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध गदर षड्यंत्र एवं आजाद हिन्द फौज के संगठन का कार्य किया। इन्होंने न केवल भारत में कई क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, अपितु विदेश में रहकर भी वह भारत को स्वतन्त्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लार्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने, गदर की साजिश रचने और बाद में जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आजाद हिंद फौज की स्थापना करने में रासबिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यद्यपि देश को स्वतन्त्र कराने के लिये किये गये उनके ये प्रयास सफल नहीं हो पाये, तथापि स्वतन्त्रता संग्राम में उनकी भूमिका का महत्व बहुत ऊँचा है। 25 मई को रासबिहारी बोस की जयंती मनायी जाती है।

रासबिहारी बोस का जन्म 25 मई 1886 को बंगाल में बर्धमान जिले के सुबालदह गाँव में हुआ था। प्रथम महायुद्ध में सशस्त्र क्रांति की जो योजना बनाई गई थी, वह रासबिहारी बोस के ही नेतृत्व में निर्मित हुई थी। सन् 1912 ई. में वाइसराय लार्ड हार्डिंग पर रासबिहारी बोस ने ही बम फेंका था। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस क्रांतिकारी तो थे ही, सर्वप्रथम आजाद हिन्द फौज के निर्माता भी थे। रास बिहारी बोस आजाद हिंद फौज के आधार स्तंभ थे। उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर उसकी कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। बीसवीं सदी के शुरूआती दशकों में जितने बड़े क्रांतिकारी षड्यंत्र हुए थे, उन सबके सूत्रधारों में शामिल थे रास बिहारी बोस। गदर रिवोल्यूशन से लेकर अलीपुर बम कांड केस तक, गर्वनर जनरल हॉर्डिंग की हत्या की प्लानिंग से लेकर मशहूर क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी के उत्तर भारत में विस्तार तक। महान क्रांतिकारी रासबिहारी बोस का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाता रहेगा। उन्होंने न केवल देश में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि विदेश में रहकर भी वह देश को आजादी दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे।

सर्वप्रथम आजाद हिन्द फौज के निर्माता रासबिहारी बोस उन लोगों में से थे जो देश से बाहर जाकर विदेशी राष्ट्रों की सहायता से अंग्रेजों के विरुद्ध वातावरण तैयार कर भारत की मुक्ति का रास्ता निकालने की सोचते रहे, सभी भारतीयों को आह्वान कर भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। रास बिहारी बोस ने 12 मई 1915 को कोलकाता छोड़ा। वे राजा पी.एन.टी. टैगोर, रवींद्रनाथ टैगोर के दूर के रिश्तेदार बनकर जापान गए। कुछ इतिहासकारों के अनुसार रवींद्रनाथ टैगोर इस छद्म रूप को जानते थे। रास बिहारी 22 मई, 1915 को सिंगापुर तथा 1915 से 1918 के बीच जून में टोकियो पहुंचे। वे एक भगौड़े के समान रहे तथा अपना निवास 17 बार बदला। इसी कालावधि में वे गदर पार्टी के हरबंस लाल गुप्ता एवं भगवान सिंह से मिले।

कश्मीर में जी-20 बैठक का कूटनीतिक संदेश

अनिल त्रिगुणायत

जम्मू-कश्मीर में जी-20 समूह की पर्यटन के वर्किंग ग्रुप की बैठक को एक महत्वपूर्ण आयोजन माना जाना चाहिए। इसमें सम्मिलित प्रतिनिधियों के बीच सदस्य देशों में पर्यटन के विकास एवं विस्तार को लेकर चर्चा हुई। श्रीनगर में इस आयोजन का सांकेतिक महत्व है क्योंकि हम कश्मीर को धरती का स्वर्ग मानते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने यहां के सौंदर्य को देखकर उचित ही कहा था कि अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है, तो यहीं है, यहीं है, यहीं है। इस आयोजन में कुछ देशों के प्रतिनिधियों के आधिकारिक रूप से शामिल नहीं होने की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि विभिन्न विषयों पर बनाये गये वर्किंग ग्रुप की जितनी बैठकें अभी तक हुई हैं, उनमें सबसे अधिक भागीदारी श्रीनगर के आयोजन में ही हुई है। प्रतिनिधियों ने भी इस बात की अहमियत को समझा है कि पर्यटन को लेकर यह बैठक उस स्थान पर हो रही है, जो एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। भारत सरकार की भी लगातार कोशिश रही है कि घाटी में स्थिति सामान्य होने की प्रक्रिया के साथ-साथ पर्यटन भी बढ़ता जाए ताकि क्षेत्रीय विकास को गति मिले। जहां तक कुछ देशों- चीन, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र- के प्रतिनिधियों के इस आयोजन में भाग नहीं लेने की बात है, तो इसे अनेक आयामों से देखा जाना चाहिए। भारत सरकार की ओर से कहा गया है कि उन देशों के निजी पर्यटन ऑपरेटरों ने बैठक में भागीदारी की है। सरकार का यह कहना भी उचित है कि किसी आयोजन में नहीं आने भर से कोई देश हमारा दुश्मन नहीं हो जाता है। संबंधों के दो स्तर हैं- जी-20 समूह में बहुपक्षीय संबंध तथा द्विपक्षीय संबंध। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक मुद्दा है और यह बहुत पुराना मसला है। इस मुद्दे पर तुर्की लंबे समय से पाकिस्तान का साथ देता आया है। अपनी उसी नीति के अनुसार उन्होंने श्रीनगर में अपना आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा। लेकिन पर्यटन ऐसी चीज है कि हर जगह से लोग दूसरी जगहों पर आते रहेंगे। तुर्की के पर्यटक भारत आते हैं, वहां से उड़ानें आती-जाती रहती हैं और जब वे श्रीनगर जायेंगे और लोगों से उनका मिलना-जुलना होगा, तो उन्हें सीधे-सीधे वास्तविकता का पता चल जायेगा। कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उसकी क्या हालत बना दी गयी है, यह दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। तुर्की और अन्य देशों का आधिकारिक रूप से नहीं आना पाकिस्तान को तुष्ट करने के लिए संदेश देने के लिहाज से अहम हो सकता है, लेकिन इसका भारत के साथ उनके संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सऊदी अरब के साथ भी यही बात है। वैसे उसके साथ भारत के रणनीतिक संबंध भी गहरे हैं। मिस्र के साथ भी हाल के वर्षों में हमारी निकटता बढ़ी है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जी-20 के आयोजनों के तहत करीब दो सौ बैठकें होनी हैं, जिनमें कई हो भी चुकी हैं। हर बैठक में हर देश के प्रतिनिधियों का आ पाना व्यावहारिक रूप से भी कठिन होता है।

पाकिस्तान और चीन ने जरूर इस मसले को लेकर बड़ा प्रचार अभियान चलाया है। चीन भी जम्मू-कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और इस क्षेत्र के लगभग बीस फीसदी हिस्से पर अवैध रूप से काबिज है। पाकिस्तान को तो वह अपने अधिकार क्षेत्र में ही मानता है और वहां अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए पाकिस्तान को तुष्ट रखने की पूरी कोशिश भी करता है। तो उनकी हरकतों का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। यह बात दुनिया के सामने जाहिर है और उसे इसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए कि समूचा जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख, चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले इलाके भी, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। इनकी संप्रभुता को लेकर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है। इससे पहले चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हुई बैठकों में भी भाग नहीं लिया था। इन जगहों पर और कश्मीर में आयोजन कर भारत ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता वाले किसी भी क्षेत्र में ऐसे आयोजन कर सकता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसी बैठकों में कोई देश आ रहा है या नहीं आ रहा है। भारत का कहना साफ है कि ये क्षेत्र हमारे अभिन्न हिस्से हैं। जी-20 के आयोजन का अवसर इसके लिए अच्छा मौका है। कुछ जगहों पर कुछ देश भले नहीं आ रहे हों, अधिकतर देश तो आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बैठकों में सभी हिस्सा ले रहे हैं, पर वर्किंग ग्रुप की बैठकों में कुछ देश अपनी राजनीति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वैश्विक भू-राजनीति में रूस-यूक्रेन युद्ध तथा पश्चिम एवं चीन व रूस की तनातनी के मसले गर्म हैं। रूस, चीन और अमेरिका जी-20 समूह के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। बड़ी बैठकों में इनका रुख क्या होता है, यह देखने लायक बात होगी। अध्यक्ष होने के नाते भारत की कोशिश सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना तथा आम सहमति से सम्मेलन का घोषणा पत्र बनाना है। इस घोषणा में तमाम बैठकों और निर्णयों का सार-संक्षेप होता है तथा उसके आधार पर समूह आगे के काम करता है।

अगले दो साल ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जी-20 की मेजबानी करेंगे। ग्लोबल साउथ के नेता होने तथा वैश्विक समुदाय में महत्वपूर्ण स्थान रखने के नाते उसमें भारत का सहकार अहम होगा। बीते दिनों जापान के हिरोशिमा में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से भेंट की। उल्लेखनीय है कि ये तीनों देश चीन और रूस के साथ ब्रिक्स में भी सदस्य हैं। उस समूह को लेकर भारत का तटस्थ रवैया है। भारत यह भी कहता रहा है कि जी-20 की भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होनी चाहिए, न कि कूटनीतिक और सामरिक तनातनी पर। जी-20 सम्मेलन से पहले भारत में ही शंघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक होनी है। इन दोनों आयोजनों में चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आने की संभावना है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आने की बात भी हो रही है। ये आयोजन सफल हों, इसकी कोशिश चीन को भी करनी चाहिए। भारत इसके लिए भी प्रयासरत है कि जी-20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल कर इस समूह को इक्कीसवीं सदी में जी-21 कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय बाद अमेरिका दौरे पर भी जाने वाले हैं। जी-20 के अध्यक्ष के रूप में भारत का रुख समावेशी रहा है।

बापू की दिनचर्या

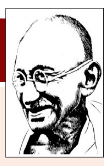

रोगी-सेवा और चिकित्सा (भाग-5)

गतांक से आगे...

उन बेचारे की आँखों से प्रेमाश्रुधारा बह रही थी। देशरत्न राजेंद्र बाबू ने जब यह प्रसंग महामना मालवीयजी को सुनाया तो वे बोले- गंगा पाप शमन करती है, चंद्रमा ताप दूर करता है, कल्पवृक्ष दैन्य का निवारण करता है, संत-महात्मा पाप, ताप और दैन्य- तीनों का नाश करते हैं। सन् 1922 में बापू की प्रथम जेलयात्रा के समय यरवदा में जेल- सुपरिंटेंडेंट ने उनकी सेवा के लिए अफ्रीका के एक सीदी (हब्शी) कैदी को नियुक्त किया। उन भाई के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। वे रोते- चिल्लाते बापू के पास आए। उन्होंने तुरंत उनके हाथ का वह भाग पानी से अच्छी तरह धोकर कपड़े से पोंछा, सुखाया और डंक की जगह वे खुद चूसने लगे। उन्होंने इतनी जोर से चूसा कि विष कम हो गया, वेदना घट गई। बाद में उन्होंने अन्य उपचार भी किया, जिससे वे बिलकुल ठीक हो गए। सेवाग्राम में तो प्रायः बिच्छुओं का उपद्रव होता। रोगियों के विशेष अस्वस्थ होने पर बापू गहरी नींद से उठकर जाते। सन् 30 में यरवदा जेल में बापू की सेवा के लिए जेल सुपरिटेंडेंट ने एक महाराष्ट्रीय कैदी को नियुक्त किया था, जो दर्द से लँगड़ाकर चला करते। जेल के सुपरिंटेंडेंट से पूछकर उन्होंने उनकी भी चिकित्सा की। इस प्रकार जेल में भी रोगी-सेवा के अवसर भगवान उनको दे देते। सन् 1936 से जब बापू वर्धा की मगनवाड़ी छोड़कर सेगाँव (सेवाग्राम) में रहने लगे, तब से आश्रम में उन्होंने सेवा की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ कीं, उनमें गाँववालों की बीमारी का इलाज और उनके स्वास्थ्य का सुधार उनकी खास प्रवृत्ति थी। आश्रम में एक-से-एक त्यागी, बुद्धिमान, विचारक और बापू की मनोभावनाओं के अनुसार काम करनेवाले लोग रहते। उन पर रोगियों की सेवा की जिम्मेदारी थी। वहाँ कनु भाई गांधी, डॉ. सुशीला बहन नैयर, प्रभाकर जी प्रभृति इस कार्य में बापू के सहायक थे। आश्रम के अन्य कई भाई-बहनों तथा गाँव के कुछ होनहार नवयुवकों को भी रोगियों की सेवा करने की तालीम दी गई और वे इस कार्य में सफल सिद्ध हुए। इसके अलावा, बापू के प्रतिनिधिस्वरूप स्वयं राष्ट्रमाता कस्तूरबा वहाँ उपस्थित रहतीं। फिर भी, बापू रोगियों की सेवा स्वयं किया करते।

क्रमशः ...

संक्षिप्त समाचार

झीरम श्रद्धांजलि दिवस पर आज मौन धारण कर देंगे श्रद्धांजलि

जगदलपुर। झीरम घाटी के नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई-बहनों की स्मृति श्रद्धांजलि दिवस पर 25 मई को शासकीय कार्यालयों में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण कर तथा शपथ लेकर राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए संकल्पित किया है।

नगर पालिका अध्यक्ष जय थवाईत द्वारा तालाब का गहरीकरण कार्य का निरीक्षण

जांजगीर चांपा। शासकीय स्कूल में अतिरिक्त कक्ष लागत राशि 16 लाख का भूमिपूजन साथ ही मंझली तालाब में हो रहे तालाब का गहरीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगरपालिका उपाध्यक्ष हरदेव देवांगन, पार्षद तमिंद्र अंजली देवांगन, देवांगन, डॉक्टर काशी प्रसाद राठौर, पद्मेश शर्मा, अभय मित्तल, गिरीश मोदी, रविंद्र राव इंगले, गौतम राठौर, नीरज देवांगन सहित नगरपालिका के इंजीनियर वार्ड वाशी उपस्थित हुए।

उतई के वार्ड क्रमांक 15 में नाली निर्माण का भूमिपूजन हुआ

दुर्ग। नगर पंचायत उतई के वार्ड क्रमांक 15 बजरंग नगर मे 22 लाख की लागत से से नाली निर्माण होगा। जिसका विधिवत पूजा-अर्चना कर भूमिपूजन किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत उतई के अध्यक्ष डिकेन्द्र हिरवानी, वार्ड पार्षद वीरेंद्र गोस्वामी पार्षद प्रहलाद वर्मा तोशन साहू एल्डरमैन खुमान साहू प्रेम नारायण साहू नगर कांग्रेस कमेटी उतई के अध्यक्ष बहादुर सिंह नेताम विधायक प्रतिनिधि भावेश साहू मुकेश साहू धनंजय नेताम तुकेश्वर ठाकुर वार्ड वासी विमल बंजारे विष्णु ठाकुर सियाराम यादव बैंक प्रबंधक श्री साहू उपस्थित थे।

जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने निकाली यातायात जागरूकता बाइक रैली

खैरागढ़। नवगठित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में जनप्रतिनिधियों और जिला व पुलिस प्रशासन के नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन इकाई खैरागढ़ ने मंगलवार को यातायात जागरूकता बाइक रैली निकाली। इस दौरान बाइक और स्कूटी में हेलमेट के साथ सवार होकर रैली का नेतृत्व विधायक यशोदा वर्मा, कलेक्टर गोपाल वर्मा और एस पी अंकिता शर्मा ने किया। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा, संगठन सदस्य, अधिकारी और नागरिक शामिल हुए। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन के बैनर तले यातायात जागरूकता रैली मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रवाना हुई। यह रैली शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए बस स्टैंड चौक, जयस्तंभ चौक, इतवारी बाजार, अमलीपारा चौक, दाऊचौरा चौक आदि का भ्रमण करते हुए अंत मे सर्किट हाउस खैरागढ़ पहुँची। यहां पर आयोजकों की ओर से रैली का विधिवत समापन किया गया। जागरूकता बाइक रैली की मुख्य अतिथि के रूप में यशोदा नीलाम्बर वर्मा, जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस प्रशासन की ओर से एसपी अंकिता शर्मा ने रैली का नेतृत्व किया।

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी, फिलहाल गर्मी से राहत नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलती दिख रही है। उत्तर पश्चिम से लगातार आ रही गर्म हवा से पारा बढ़ रहा है। जिससे प्रदेश का अधिकतम तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार हो चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान धमतरी में 46.8 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं रायपुर में 41.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। अंबिकापुर में 41।8, कोरबा में 41.3, बिलासपुर में 43.4, रायगढ़ में 44.3 डिग्री तापमान दर्ज किया किया गया है। जगदलपुर में 36.2, दुर्ग में 42 और राजनांदगांव में 39.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। जानकारों के मुताबिक 90 दिनों की गर्मी में छत्तीसगढ़ के मध्यक्षेत्र का आधे से ज्यादा दिन तपता है। जिसमें बिलासपुर 48 दिनों तक गर्म रहता है। रायपुर 45 दिनों तक, दुर्ग 42 दिनों तक, जगदलपुर 10 दिनों तक गर्म रहता है। सबसे ज्यादा लू 16 दिनों तक राजनांदगांव में चलती है।

बस्तर की बेटियों ने रचा इतिहास, जोरों शोरों से हुआ स्वागत

जगदलपुर। 6वीं राष्ट्रीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिनांक 17 से 21 मई 2023 तक आयोजित हुई। जिसमें बस्तर जिला और बस्तर मार्शल आर्ट्स अकादमी की बेटियों ने 5 स्वर्ण और एक कांस्य पदक प्राप्त किया जिसमे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी पलक नाग ने फिर से सीनियर वेल्टर वेट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, वही माही डोंगरे ने यूथ सी 57 किग्रा स्वर्ण पदक, येजीन श्रेया सुना ने यूथ सी 44किग्रा स्वर्ण पदक, तनुप्रिया दत्ता ने यूथ बी 44 कि.ग्रा. स्वर्ण पदक, सेमीकॉन्टेक्ट में श्रिया शर्मा ने बॉटम वेट में स्वर्ण पदक और माही मेश्राम ने यूथ ए 52 किग्रा. में कांस्य पदक प्राप्त किया। इन सभी खिलाडियों के प्रथम आगमन पर शहर में जोरों शोरों से स्वागत किया गया। ये सभी खिलाड़ी बस्तर मार्शल आर्ट अकादमी में प्रैक्टिस करते है ये दूसरा साल है जिसमें मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में बस्तर की बेटियों ने अपना जौहर दिखाया है और इतिहास रच रही है।

75 प्रतिशत स्कूलों में नहीं हो रहा आरटीई का पालन

स्ट्रेनथिंग स्कूल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़, इश्यू एंड चैलेंजेस विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

■ **छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के अलावा दिल्ली और उत्तरप्रदेश के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल**

रायपुर। आरटीई फोरम और आर्थिक अनुसंधान केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में %स्ट्रेनथिंग स्कूल एजुकेशन इन छत्तीसगढ़ इश्यू एंड चैलेंजेस% विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को राजधानी के जयस्तंभ चौक स्थित होटल सोलिटेयर में किया गया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ के 20 जिलों के अलावा दिल्ली और उत्तरप्रदेश के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि हुए शामिल।

कार्यशाला में नेशनल काउंसिल फ़ॉर एजुकेशन, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संयोजक रमाकांत राय ने बताया कि देश के केवल 25 प्रतिशत विद्यालय ही शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) का पालन करते हैं। छत्तीसगढ़ में यह 25.2 प्रतिशत है। यानी कि 75 प्रतिशत स्कूल आरटीई का पालन नहीं होता। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि देश में 6-14 साल के कुल 14.8 प्रतिशत बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में 6.6 प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ नॉन गवर्मेन्ट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2020 और केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए उसकी खामियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब पालकों, शिक्षक संगठन, शिक्षाविद एवं सिविल सोसायटी के लोगों को निजी स्कूलों के खिलाफ खुलकर सामने आना चाहिए और निजी स्कूलों को नियंत्रित करने अपने विधायकों के जरिये विधानसभाओं में मुद्दा उठाना चाहिए।

कार्यशाला के प्रारंभ में आरटीई फोरम के राष्ट्रीय संयोजक गौतम बंदोपाध्याय ने शिक्षा का परिदृश्य और छत्तीसगढ़ के मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समय है, जब शिक्षा पर हमला हो रहा है। सरकारी स्कूलों को खराब बताकर प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के मर्जर से हजारों की संख्या में स्कूल बंद हुए हैं। इससे ड्राप आउट बच्चों की संख्या बढ़ी हैं। उन्होंने विकलांगों, विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। आरटीई फोरम नई दिल्ली कीसह संयोजक एंजेला तनेजा ने कार्यशाला में ऑनलाइन जुड़कर आरटीई और छतीसगढ़ नॉन गवर्मेंट स्कूल फी रेगुलेशन एक्ट 2020 की खामियों को रेखांकित करते हुए उन खामियों को दूर करने के उपायों पर विस्तार से बात रखी।

बालक-पालक समिति की अध्यक्ष विजय लक्ष्मी ठाकुर ने कहा कि शासकीय स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए। प्रत्येक स्कूल में खेल ग्राउंड और खेल शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। गणेशनगर स्कूल, बिलासपुर की एसएमसी अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सोनवानी ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होती। बेहद कम तनख्वाह में शिक्षक नौकरी करते हैं। मोटी फीस लेने के बाद भी निजी स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने में नाकाम हैं। बिलासपुर के ही फिरदियुस एक्का ने कहा कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं हैं। ऊपर से उन शिक्षकों के ऊपर अन्य कई तरह के सरकारी काम सौंप दिए जाते हैं, इससे शिक्षा की गुणवत्ता तो खराब है और इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है। कोंडागांव, बस्तर से आये भूपेश तिवारी ने निजी स्कूलों द्वारा नियमों के उलंघन, सुविधाएं न देने और पूरी फीस वसूलने के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कार्यशाला में नई दिल्ली आरटीई फोरम कार्यालय के सचिव मित्ररंजन ने सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2023 पर विचार रखे।

पटवारियों की हड़ताल का असर आम जनता पर

मनेन्द्रगढ़। प्रदेश राजस्व पटवारी संघ द्वारा 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है।पटवारियों की इस हड़ताल का असर अब मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी -भरतपुर जिले मे भी देखा जा सकता है।राजस्व का कामकाज पूरी तरह से बंद होने के कारण ग्रामीण, किसान और आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ।पटवारियों के इस हड़ताल का आलम यह है कि जिला मुख्यालय सहित मनेन्द्रगढ़ -चिरमिरी -भरतपुर जिले के तमाम तहसील कार्यालयों मे सन्नाटा पसरा हुआ है।पटवारियों के हड़ताल पर जाने से जमीनी सीमांकन, नामांतरण आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र ,बंटवारा सहित कई प्रकार के काम पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं।तहसील आ रहे लोगो को निराश होकर अपने अधूरे काम के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि वेतन विसंगति , सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति देने, संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, और मुख्यालय मे निवास की बाध्यता खत्म करने और विभागीय जांच के बिना एफ्आईआर दर्ज नही करने जैसे 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी आंदोलन कब तक चलेगा और कब तब आम नागरिकों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा,इधर 8 सूत्रीय मांगो को लेकर धरने मे सुरेंद्र पाल सिंह प्रांतीय उपाध्यक्ष, गिरजेश साहू जिलाध्यक्ष,नागेंद्र नारायण सिंह,रमेश राम बाबू, नारायण सिंह, नलिन तिवारी, दीपेंद्र पाल सिंह, सुनैना सिंह, सरस्वती गुप्ता, रंजीता लकड़ा, छाया गुप्ता, मंजुलता, चंदा भगत, प्रेमारोस खाखा, पुत्तरा सिंह, वंदना तेंदुवा आदि उपस्थित रहे।

एनएसयूआई प्रदेश सचिव पर किया घातक हथियार से वार

रायपुर। रायपुर के डीडी नगर इलाके में गोल चौक पर एनएसयूआई प्रदेश सचिव पर एक बदमाश और उसके साथी ने नुकीले हथियार से हमला किया है। इससे बुरी तरह से घायल प्रदेश सचिव को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बीती देर रात हमला करने वाला ओम दुबे और उसके साथी मौके से फरार हो गए। एनएसयूआई प्रदेश सचिव मेहताभ हुसैन और उसके साथ देर रात में चौक में खड़े थे , तभी दो बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि बदमाश ओम दुबे और उसका साथी रवि चौक पर पहुंचे। पुराने बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और ओम दुबे ने मेहताभ को पास के दुकान वाले से कैचीनुमा चीज से मेहताब के जांघ पर वार कर दिया। घटना के बाद ओम दुबे और उसके साथी वहां से फरार हो गए। मेहताब ने पुलिस थाना डीडी नगर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के तुरंत बाद पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू की। देर रात तक डीडी नगर पुलिस ने ओम साहू और उसके साथी रवि को पकड़ा। ओम साहू आदतन अपराधी है, उसके थाने में मारपीट के दस से अधिक मामले दर्ज हैं।

शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है, जिसके जरिये हम अपने सपनों को कर सकते हैं साकार

रायपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में आयोजित पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, अन्तरिक्ष वैज्ञानिक पद्म श्री प्रो. राजन, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है, शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है, जिसके जरिये हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। छह दशकों से विश्वविद्यालय ने गौरवपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। बस्तर, सरगुजा के वनांचलों में जहां जरूरी हुआ वहां महाविद्यालय खोले गए।

मुख्यमंत्री ने दीक्षांत समारोह के मुख्य वक्ता प्रो. वाई.एस. राजन का छत्तीसगढ़ में स्वागत करते हुए कहा कि प्रॉफेसर राजन ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान को अपने नवाचारों द्वारा नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारा सौभाग्य है कि भारतरत्न ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी के निकटतम सहयोगी रह चुके प्रसिद्ध अन्तरिक्ष वैज्ञानिक पद्म श्री प्रो. राजन आज के दीक्षांत समारोह में हमारे बीच हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है, जिसके जरिये हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीक्षांत समारोह में 76 प्रतिशत बेटियां उपस्थित हैं। यह नारी के सशक्त होने का प्रतीक है। महिलाएं अब अबला नहीं सबला बन रही हैं।

जहां कांग्रेस की सरकार, वहां बदले की भावना से कर रही काम : फूलोदेवी नेताम

बिलासपुर। राज्यसभा सांसद और छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने ईडी पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। कहा कि, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ईडी बहुत परेशान कर रही है। महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार थी तो ईडी उनसे भिड़ी हुई थी। भाजपा का नाम लिए बिना कहा कि, तोड़फोड़ करके उनकी सरकार आई तो जिन पर कार्रवाई हो रही थी, उन्हें छोड़ दिया गया। अब छत्तीसगढ़ को टारगेट बनाया गया है, लेकिन यहां की जनता जान गई है कि भाजपा की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सांसद नेताम बिलासपुर में मीडिया से बात कर रहीं थीं।

ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मिले टिकट

महिला कांग्रेस की जिला व ब्लाक पदाधिकारियों की मंगलवार देर शाम बैठक लेने पहुंची सांसद नेताम ने कहा कि, इस बार के चुनाव में भी महिलाएं संगठित हैं। महिलाएं मजबूत हैं। कहा कि, बूथ लेवल की कमेटी गठन किया जाना है। निश्चित तौर पर उनको जवाबदारी दी जाएगी, जो ईमानदारी से काम करेंगी। पूरे देश में प्रतिशत के आधार पर भी देखें तो सबसे ज्यादा महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है। उन्होंने कहा कि, महिला होने के नाते मैं चाहूंगी और हाईकमान से भी बात करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारे। वे यह लड़ाई निश्चित तौर पर जीत की आएंगी।

पहलवानों पर कहा, हमारा देश खतरे में है

राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने दिल्ली में पहलवानों के चल रहे प्रदर्शन को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि, हमारा देश आज खतरे में है। जो पहलवान पहलवानी दिखाकर भारत का नाम रोशन करते हों, हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाते हैं और शान से कहते हैं हम भारत के निवासी हैं। वही भारत देश को रोशन करने वाले आज धरने पर हैं। निश्चित तौर पर हम उनके मांग में उनके साथ हैं। उनको न्याय मिलना चाहिए। कहा कि जो दोषी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहलवान बहुत दिनों से धरने पर हैं, लेकिन न तो एफआईआर हो रही और न ही कार्रवाई।

प्रदेश में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाया जाये : डॉ. मिश्र

रायपुर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा कि राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के गैंदाटोला क्षेत्र के टिपानगढ़ से सामाजिक बहिष्कार की एक घटना सामने आई है जिसमें एक परिवार ने ग्रामीणों द्वारा सामाजिक बहिष्कार से परेशान होकर खुद को मकान में ही बंद कर लिया, बताया जाता है कि टिपानगढ़ के साहू परिवार की सदस्य सुखबती बाई, चेतन साहू और 7 साल की खुशबू साहू ग्रामीणों के द्वारा बहिष्कार से परेशान होकर कई दिनों से मकान में बंद थी। कई दिनों तक घर का दरवाजा न खुलने पर बाद सभी को गम्भीर हालत में छुरिया सामुदायिक अस्पताल लाया गया, जहां 50 साल की सुखबती की उपचार के दौरान मौत हो गई।

डॉ दिनेश मिश्र ने कहा हमारे यहाँ सामाजिक और जातिगत स्तर पर सक्रिय पंचायतों द्वारा सामाजिक बहिष्कार के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। ग्रामीण अँचल में ऐसी घटनाएँ बहुतायत से होती है जिसमें जाति व समाज से बाहर विवाह करने, समाज के मुखिया का कहना न मानने, पंचायतों के मनमाने फरमान व फैसलों को सिर झुकाकर न पालन करने पर किसी व्यक्ति या उसके पूरे परिवार को समाज व जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है व उसका समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। कुछ मामलों में तो स्वच्छता मित्र बनने पर, तो कहीं आर.टी.आई. लगाने पर भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में 30 हजार से अधिक व्यक्ति सामाजिक बहिष्कार जैसी कुरीति के शिकार हैं। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति सामाजिक बहिष्कार जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जनजागरण एवं प्रताड़ित लोगों की मदद के लिए पिछले कुछ वर्षों से लगातार कार्य कर रही है और कुछ परिवारों का बहिष्कार समाप्त करने में सफल भी हुई है,पर बहिष्कृत परिवारों की संख्या बहुत अधिक है और उनका पुनः समाज में शामिल होना, पुनर्वास के लिए एक सक्षम कानून की आवश्यकता है. समिति सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर आगामी विधानसभा सत्र में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाने की मांग की है। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञात हो , महाराष्ट्र विधानसभा में सभी सदस्यो ने सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में महत्वपूर्ण कानून को बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से11 अप्रैल 2016 को पारित कर दिया तथा 20 जून 2017 को माननीय राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 3 जुलाई 2017 से पूरे महाराष्ट्र में लागू कर दिया गया ।इसी प्रकार हमारे प्रदेश में भी सामाजिक बहिष्कार प्रतिषेध अधिनियम की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है। डॉ. मिश्र ने कहा कि सामाजिकक बहिष्कार होने से दंडित व्यक्ति व उसका परिवार गाँव में बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है। पूरे गाँव-समाज में कोई भी व्यक्ति बहिष्कृत परिवार से न ही ककोई बातचीत करता है और न ही उससे किसी प्रकार का व्यवहार रखता है।

अब वनांचल के लोग वनकर्मियों को दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त मानते हैं : बघेल

■ **भारत सरकार के विशेष सचिव ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा 'अन्य राज्यों से बेहतर कार्य छत्तीसगढ़ में हुआ**

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने मंगलवार शाम रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्शी कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित है लेकिन सभी के साथ जंगल में रहने वाली लोगों की चिंता भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि भू-जल स्तर पर्याप्त होना चाहिए। हमारी सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में नरवा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण और जल संवर्धन के लिए वनांचल में 1 करोड़ 19 लाख संरचनाओं का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान वे जहां भी गए सभी से इस योजना के संबंध में जानकारी ली, तो सभी का एक ही जवाब मिला नरवा योजना अच्छी है। हर जगह आदिवासियों ने नरवा योजना को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव के लोग और वनसंरक्षकों की दोस्ती हो गई है। आदिवासी और वनांचल में रहने वाले लोग वन विभाग को अपना दुश्मन नहीं मानते। वन विभाग के अधिकारी जंगल जाते है तो लगता है, हमारे लिए कोई नई योजना आयी है, छत्तीसगढ़ में यह परिवर्तन आया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगल में ऐसे वृक्ष लगाएं जो वनांचल में रहने वालों के लिए लाभदायक हो। जंगल में फल देने वाले वृक्ष जरूर लगाने चाहिए। इसके साथ ही इनकी बिक्री की व्यवस्था भी होनी चाहिए। वन विभाग सिर्फ जंगल का अभिभावक नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोगों का भी अभिभावक है। ऐसे आपसी संबंध विकसित करने में हम सफल रहे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फलदार वृक्षों को बढ़ावा देने से आमदनी बढ़ेगी, हरियाली रहेगी और जंगल भी बचे रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय ऑक्सीजन के महत्व का पता चला। छत्तीसगढ़ से देश के कई इलाको में ऑक्सीजन पहुंचायी गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 67 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी हो रही है। जिससे लघु वनोपज संग्राहकों को लाभ अर्जित हो रहा है।

भारत सरकार में वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक श्री चन्द्रप्रकाश गोयल ने मृदा एवं जल संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में भूमि एवं जल संरक्षण में बेहतर कार्य हो रहा है।

कार्यशाला में देश भर के वानिकी विशेषज्ञ शामिल हुए और छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं सवंर्धित करने पर चर्चा हुई। इस अवसर पर वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सिंह सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के विशेष सचिव एवं महानिदेशक हैं श्री चंद्र प्रकाश गोयल, राष्ट्रीय कैम्पा के सीईओ श्री सुभाष सिंह, वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, पीसीसीएफ श्री वी. श्रीनिवास राव, सहित देश भर से आए वानिकी विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।

कांग्रेस छुपाना चाहती है झीरम का सच: साव

पीएससी घोटाले ने युवाओं का भविष्य और उनका आत्मविश्वास तोड़ा

रायपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा अनुमान तो था, लेकिन यह घोटाला इतना बड़ा होगा, इसकी हमें भी कल्पना नहीं थी। शुरुआती आकलन में अनुसार इस योजना में 1300 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई है, यह आगे इससे भी बड़ा घोटाला है। अगर इनके फ्लैगशिप योजना के साथ ऐसा हुआ है तो आप अन्य योजना की कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस यह घोटाला पकड़े जाने पर अभिमान अभियान चला रही है, हर घोटाला कांग्रेस के लिए अभिमान ही होता है, पर छत्तीसगढ़ शर्मसार है कांग्रेस के घोटालों से।

जहां तक गौ माता का सवाल है तो इस मामले में संसद कूच कर रहे गोभक्त संतों को गोलियों से भून देने वाली कांग्रेस, दक्षिण में बक़ायदा गौ हत्या कर उसका मांस प्रदर्शनी लगा कर खाने वाले लोग अगर आज अपना गौ प्रेम दिखा रहे, तो और क्या कहा जा सकता है? ऐसे घोटालों से छत्तीसगढ़ शर्मिंदा है। गौठान के नाम पर भूपेश बघेल जी की सरकार ने घोटालों की पराकाष्ठा पार कर दी है। भूपेश बघेल जी ने दावा किया था कि प्रत्येक गौठान में 19 लाख रूपए का खर्चा किया गया है। हमने भी गौठान देखे। प्रदेश के हर जिले में सभी गौठानों का दौरा किया। उसी निरीक्षण में भूपेश बघेल जी के झूठों का पर्दाफाश हो गया। वही खामियां को ग्रामीण गिना रहे थे, आज प्रदेशवासियों और मीडिया के साथियों ने भी देख ली।

पीएससी घोटाले पर श्री साव ने कहा कि पीएससी घोटाले ने प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य और उनका आत्मविश्वास तोड़ कर रख दिया है। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था पर भरोसा की बदौलत ही लाखों युवा अपनी जवानी समर्पित कर देते हैं, उनका विश्वास जिस तरह टूटा है, यह काफी खतरनाक है। जैसा भाई भतीजावाद किया गया है इस मामले में, वह दुखद है। छत्तीसगढ़ शर्मसार है इससे। भाजपा लगातार युवाओं की इस पीड़ा को सदन से लेकर सड़क पर उठा रही है। हम संवैधानिक समेत अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। इस घोटाले के खिलाफ युवाओं के संघर्ष को हम अंजाम तक पहुँचायेंगें।

झीरम मामला = श्री अरुण साव ने कहा कि जिस तरह भूपेश बघेल इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष रहने से लेकर आजतक झूठ फैला रहे हैं, जैसी बयानबाज़ी कर रहे हैं, उससे यह कहने को विवश हैं कि कांग्रेस खुद सच को छुपाना चाहती है हम पूरी ज़िम्मेदारी के साथ यह बात कह रहे हैं,आखि़र जिस झीरम का सबूत जेब में होने का भूपेश जी दावा करते थे, वह सबूत कहां छोड़ आये हैं वे, किसे दे आये, कहां छिपा आये, यह बड़ा सवाल है।

राष्ट्रीय रामायण आयोजन = कालनेमि ने भी राम-राम बोला था, लेकिन राम जी भक्ति के लिए नहीं, बल्कि हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए। कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठना लाजिमी है। क्योंकि, रामसेतु के अस्तित्व को नकारा, भगवान राम को काल्पनिक बताया। श्रीराम मंदिर का विरोध किया। छत्तीसगढ़ में उस भगवा ध्वज का अपमान जिसे भगवान राम अपने रथ पर लगाते थे। हिन्दु संस्कृति का विरोध करने वाले को कांग्रेस का समर्थन। हिन्दु समाज के युवा भुनेश्वर साहू की हत्या पर उन्हें न्याय न मिलना।

जीरम का सच सामने लाने एनआईए रमन सिंह, मुकेश गुप्ता का नार्को टेस्ट करायेः कांग्रेस

रायपुर। जीरम शहादत की 10वीं वर्षगांठ के समय भाजपा नेताओं द्वारा की गयी बयानबाजी बेहद ही स्तरहीन और आपत्तिजनक है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भाजपा प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने जीरम मामले में बयानबाजी कर भाजपा बेशर्म चरित्र को प्रदर्शित किया है। झीरम घाटी हमला एक ऐसा हत्या कांड था जिसने कांग्रेस के नेतृत्व की एक पूरी पीढ़ी को ही समाप्त कर दिया था। स्वतंत्र भारत में हुई दुर्दान्त और हृदय विदारक घटना भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में डॉ. रमन सिंह के राज में घटित हुई थी। इस क्रूर हत्याकांड के लिये भाजपा और उसकी राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस मामले में खुलासे के लिये जरूरी है कि रमन सिंह सहित तत्कालीन गृह मंत्री, तत्कालीन जिम्मेदार पुलिस के अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराया जाये। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा जीरम की जांच नहीं होने देना चाहती है। जीरम न्यायिक आयोग की जांच पर रोक का पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक स्टे लेकर आये थे है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा से जवाब मांगा-

■ जीरम की सच्चाई सामने लाने एनआईए जीरम की फाइल एसआईटी को सौंपे

भाजपा जवाब दें: भाजपा बतायें कि कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा को घोर नक्सल इलाकों से क्यों हटा दिया गया था? यात्रा की सुरक्षा हटाने के आदेश किस अधिकारी ने दिया था? यात्रा की सुरक्षा हटाने के लिये किस नेता ने अधिकारी से कहा था? जीरम शहीदों के पीड़ित परिवार उस समय सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे विधानसभा में घोषणा के बाद भी रमन सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा क्यों नहीं किया था? जीरम के पीड़ित परिवारों को तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह मिलने के लिये क्यों रोक दिया गया था?

मुझमें कितने राज हैं बतलाऊं क्या... बंद एक मुद्दत से हूं,खुल जाऊं क्या...

शंकर पांडे

जीरम घाटी नक्सली हमले को 25 मई को10 साले पूरे हो जाएंगे, परंतु दुर्भाग्य यह है कि नक्सली हमले के गुनहगार अभी भी कानून की पकड़ से बाहर है। वैसे छग में भूपेश सरकार के गठन के बाद इस मामले के खुलासे की उम्मीद बँधी थी पर जांच की ही दिशा नहीं पकड़ सकी है।बस्तर की जीरम घाटी की नक्सली वारदात ने पूरे देश को हिला दिया था। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा,पूर्व विधायक उदय मुदलियार जैसे दिग्गज नेताओं सहित 31 लोगों का जीवन नक्सलियों ने लील लिया था। उस समय तत्कालीन प्रदेश की भाजपा सरकार की सुरक्षा चूक सहित राजनीतिक साजिश की चर्चा के बीच कई अनसुलझी बात अभी तक चर्चा में है।वैसे यह तय था कि बस्तर के टाईगर महेन्द्र कर्मा तो नक्सली निशाने पर शुरू से रहे थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल तथा पूर्व विधायक उदय मुदलियार तो सामूहिक गोलीबारी के अनजाने में शिकार हो गये पर कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल को अलग लेजाकर नक्सलियों ने क्यों हत्या कर दी? उन्हें दूर ले जाकर आखिर नक्सली क्या जानना चाहते थे? सवाल यह भी उठ रहा था कि सुकमा जिले निकली परिवर्तन यात्रा में तो सुरक्षा इंतजाम था पर जगदलपुर जिले में सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं था...? जहां नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था वह राष्ट्रीय राजमार्ग था। जहां विद्याचरण शुक्ल नक्सली हमले के बाद घायल अवस्था में जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहे वहां से 10 किलोमीटर के दायरे में 2 पुलिस थाने थे फिर विद्याचरण शुक्ल जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री के पास 4 घंटे बाद पुलिस पहुंच सकी? क्या यह नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लडनें की नियत पर सवाल नहीं खड़ा करता है....! हालांकि तत्कालीन सरकार ने गणेश उइके,गुडसा उसेण्डी, रमन्ना, सुमित्रा और पांडू सहित लगभग 60 महिला सहित 200 लोगों के शामिल होने का दरभा थाने में मामला दर्ज किया,तेलंगाना में संदिग्ध नक्सली पकड़े भी गये पर उनसे भी एन आई ए ने पूछताछ की जरूरत नहीं समझी......? वैसे पूरे मामले की एनआईए जांच भी हुई पर जाँच से क्या निकला, उसका खुलासा नहीं हो सका,छग सरकार ने एसआई टी जाँच के लिये उस जाँच रिपोर्ट माँगा गया पर उसे भी सुलभ नहीं कराई गई ? कांग्रेस के एक नेता को दरभा नक्सली वारदात के 2 दिन पहले दिनेश पटेल का एक एसएमएस?भी मिलने की भी चर्चा हुई थी जिसमें तत्कालीन प्रदेश सरकार के मुखिया के खिलाफ खुलासे का जिक्र था..? उसका क्या हुआ...बहरहाल नंदकुमार पटेल के दूसरे पुत्र उमेश पटेल वर्तमान में भूपेश मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, महेन्द्र कर्मा की पत्नी देवती कर्मा सत्ताधारी दल कांग्रेस की विधायक हैं।इस वारदात में किसी तरह निकले कवासी लखमा,अभी छग सरकार में मंत्री हैं. नक्सली वारदात के समय बस्तर पुलिस महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ पुलिस अफसर अच्छे पदों पर हैं, कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो इन अफसरों पर भी कार्यवाही की मांग करती रही थी। बहरहाल भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मामले में एसआईटी की घोषणा की थी पर एनआईए ने फाईल देने से मना कर दिया और जांच लटक गई है। भूपेश सरकार ने जाँच के लिये एसआईटी की घोषणा की और भाजपा के एक बड़े नेता हाईकोर्ट पहुंच गये क्यों..?क्या जीरम घाटी नक्सल हमले का कभी खुलासा हो सकेगा...?

रोजगार पंजीयन, नवीनीकरण के आवेदन ऑनलाईन, तीन महीने सत्यापन की सीमा

रायपुर। रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। राज्य शासन ने रोजगार पंजीयन और नवीनीकरण के लिए आवेदन करने ऑनलाईन व्यवस्था की है। शिक्षित बेरोजगार युवा वेबसाइट www.e&change.cg.nic.in/e&change पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन और नवीनीकरण के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। जिले के रोजगार कार्यालय के उप संचालक ने बताया कि रोजगार पंजीयन और नवीनीकरण संबंधित सभी आवेदन केवल ऑनलाईन ही लिए जाते है। इन आवेदनों को तीन महिनें की समय अवधि में सत्यापन कराना होता है।

पंजीयन और नवीनीकरण के आवेदनों को रोजगार कार्यालयों में ऑफलाईन स्वीकार नहीं किया जाता है इसलिए ऐसे आवेदन करने युवाओं को रोजगार कार्यालय में उपस्थित होना जरूरी नहीं है।उप संचालक ने बताया कि ऑनलाईन किए गए आवेदन अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन कराने की अवधि तीन महिनें की है। युवाओं का आवेदन तीन महिनें तक वैध होता है। युवा अपने सुविधा अनुसार कार्यालयीन समय में तीन महिनें में किसी भी दिन रोजगार कार्यालय आकर सत्यापन करा सकते है।

मृदा एवं जल संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

रायपुर, 24 मई 2023/ वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में रायपुर में मृदा एवं जल संरक्षण पर आयोजित कार्यशाला में आज मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके तहत देश के विभिन्न राज्यों के वन विभाग के अधिकारियों, केन्द्रीय टीम और वानिकी विशेषज्ञों ने प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के संबंध में परिचर्चा में हिस्सा लिया।

■ प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित एवं संवर्धित करने के संबंध में हुई चर्चा

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीसीसीएफ श्री व्ही. श्रीनिवास राव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम को भू-जल संवर्धन के लिए तेजी से संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नरवा कार्यक्रम अंतर्गत अब तक 6395 नालों को पुनर्जीवित कर 22 लाख 92 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जा चुका है। कार्यशाला में इन उपलब्धियों के बारे में प्रेजेंटेशन दिया गया तथा नरवा विकास कार्यक्रम के विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा की गई।

कार्यशाला में पीसीसीएफ एवं प्रबंध संचालक राज्य लघुवनोपज संघ श्री अनिल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के वन उत्पादों से आय की असीम संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा के अनुरूप 65 प्रकार के वनोत्पादों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर उनका वैल्यूएडिशन एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न वन उत्पादों का वैल्यूएडिशन कर सी-मार्ट के जरिये उनकी बिक्री भी की जा रही है, जिससे वनांचल में रहने वाले लोगों को रोजगार मिल रहा है और उनकी आमदनी भी सुनिश्चित हो रही है। श्री अनिल राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन का भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। कार्यशाला में एपीसीसीएफ श्री अरुण पांडेय ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की तारीफ करते हुए कहा कि इस योजना से मुख्यमंत्री की मंशानुरूप फलदार वृक्षों को प्रोत्साहन मिल रहा है तथा वनावरण में भी वृद्धि हो रही है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

कांग्रेस राज में क्या हालात है? अपराधी सर काटकर गाड़ी में घुमा रहे हैः कौशिक

रायपुर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने बलौदा बाजार के सरसिंवा में हुए हत्या को लेकर सरकार की निष्क्रियता को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ आबादी के दृष्टिकोण से देश में 22 वें नंबर का राज्य है। परंतु अपराध में यह टॉप 10 पर है।

पूरे प्रदेश में सुपारी किलिंग से लेकर लूटपाट, चाकूबाजी, मारपीट, हत्या की कोशिश और हत्याओं की वारदातें इस तेजी से बढ़ रही हैं कि पूरे प्रदेश में आम लोगों की सुरक्षा दाँव पर लग गई है और लोगों का घर से निकलना और सुरक्षित वापस घर पहुंचना मुश्किल हो गया है।जिस तरह से अपराधी संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस एक तरह से अपराध के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी अपराधियों का केन्द्र बिंदु बन गया है और प्रदेश का हर शहर अपराधों का शहर हो गया है। बलौदा बजार के सरसिंवा में हुआ हत्याकांड प्रदेश के लिये चिंता का विषय है जहां अपराधी अपराध करके कटा हुआ सर लेके खुलेआम घुम रहा है और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी ही नहीं है। यह घटना अकेली ऐसी घटना नहीं है, कांग्रेस के राज में ऐसी अनेक घटनाएं हुई है।

परहित उपदेश कुशल बहुतेरे राजेश मूणत अपने गिरेबांन में झांके

रायपुर। मोदी सरकार यदि आरबीआई की बात मानती तो नोटबंदी ही नहीं होता 2000 के नोट भी नही छापे जाते

रायपुर/24 मई 2023। भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूणत के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत पहले खुद की भाषा शैली को सुधारें फिर ज्ञान बाटे। राजेश मूणत की भाषा शैली से पूरा प्रदेश परिचित है। भाजपा के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस के नेता और पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के लिये कई बार राजेश मूणत ने अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। असंसदीय भाषाओं का प्रयोग किया है जिसके चलते पूरे प्रदेश में राजेश मूणत की थु थु हुई है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सोशल मीडिया में राजेश मूणत के अनेक वीडियो है जिसमें वो भाजपा कार्यकर्ताओं को गाली देते हुए किसी में पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों से अभद्रता करते हुए किसी में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अशोभनीय ने टिप्पणी करते हुए देखे और सुने जा सकते हैं तो पहले राजेश मूणत खुद के व्यवहार और संस्कार को ठीक करें फिर सलाह दें प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि नोटबंदी के दौरान 1000 के नोट को बंद कर उसके स्थान पर 2000 रु. नोट छापना ही मूर्खतापूर्ण निर्णय था।

हज यात्रियों ने सीखा उमरा अदा करना

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने बताया कि हज 2023 के लिए आज रायपुर में रायपुर संभाग से जाने वाले हज यात्रियों का एक दिवसीय हज ट्रेनिंग का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी द्वारा आयोजित किया गया। इसमे रायपुर संभाग के हज यात्रियों को हज यात्रा की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष खनिज विकास निगम श्री गिरीश देवांगन ने हज यात्रियों को यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि, पवित्र इबादत हेतु जाने वाले यात्रियों को हर संभव मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराना छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य हज कमेटी द्वारा हज यात्रियों को पूर्ण प्रशिक्षित किये जाने हेतु अपने कार्यदायित्वो का निर्वहन बखूबी किया जा रहा है, जो प्रशंसनीय है। विधायक एवं अध्यक्ष गृह निर्माण मंडल श्री कुलदीप जुनेजा ने सभी हज यात्रियों को सफर-ए-हज की मुबारकबाद दी। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम खान ने हज यात्रियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के हज यात्रियों को फ़रीज़ए हज की मुकम्मल अदायगी के लिए हर संभव सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। हज यात्रा को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाये जाने हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश के हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया।

भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक संपन्न

रायपुर। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश कार्यसमिति बैठक भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अरूण साव, प्रदेश महामंत्री संगठन पवन साय, छत्तीसगढ़ प्रभारी मो. सद्दाम, प्रदेश प्रभारी डॉ. सलीम राज, आरिफ खान, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष शकील अहमद ने प्रदेश कार्यसमिति बैठक में आये पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरूण साव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा मोर्चा को जो जिम्मेदारी दी है उसे सभी कार्यकर्ताओं ने तन्मतया से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर तरफ माफिया, दलाल एवं भ्रष्टाचार सक्रिय है और यही प्रदेश की कांग्रेस एवं सरकार को चला रहे है। यह सबको पता है कि प्रदेश में कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है चाहे वह कोयले की दलाली हो या फिर शराब में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला हो, इस सरकार की केवल एक ही नीति है प्रदेश को लूटना और गांधी परिवार को खुश करना।श्री साव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया एक परिवार में अपना नंबर बढ़ाने के लिए प्रदेश का पैसा मिस्टर कलेक्शन मास्टर बन कर पूरा कर रहे हैं।

जनजातीय वाचन में राजधानी तीन दिन रहेगा सराबोर

रायपुर। आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और उनके अभिलेखीकरण के उद्देश्य से तीन दिवसीय ''जनजातीय वाचिकोत्सव 2023'' का आयोजन 25 मई से नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया जा रहा है। मंत्री आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के मुख्य आतिथ्य और संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव के अध्यक्षता में 25 मई को ''जनजातीय वाचिकोत्सव 2023'' का शुभारंभ होगा। तीन दिवसीय यह आयोजन 25 मई से 27 मई तक चलेगा, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय वाचकों द्वारा जनजातीय वाचिक परंपरा की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। आयोजन आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के सहयोग से किया जा रहा है। विषयानुसार प्रथम दिवस 25 मई को जनजातीय देवी-देवता एवं मड़ई मेला के संबंध में वाचिक ज्ञान, जनजातियों में प्रचलित लोक कहानियाँ, कहावतें एवं लोकोक्तियां, जनजातीय लोकगीत, उनका अभिप्राय एवं भावार्थ विषय पर जनजातीय वाचन किया जाएगा। द्वितीय दिवस 26 मई को ''जनजातीय तीज-त्यौहार एवं वाचिक परम्परा, जनजातीय जीवन संस्कार संबंधी वाचिक परम्परा एवं जनजातीय समुदाय की उत्पत्ति संबंधी धारणा एवं वाचिक परंपरा विषय पर जनजातीय वाचन किया जाएगा।

मृदा एवं जल संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला

■ कार्यशाला में मिट्टी और नमी संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों पर विस्तार से हुई चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'नरवा विकास कार्यक्रम' अंतर्गत वन क्षेत्रों में स्थित 6 हजार 395 नालों को पुरर्जीवित किया जा चुका है। इसके तहत इन नालों में 774 करोड़ रूपए की राशि से अब तक एक करोड़ 19 लाख 84 हजार भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे 22 लाख 92 हजार हेक्टेयर क्षेत्र उपचारित हुआ है।

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तत्वाधान में मृदा-जल संरक्षण पर राजधानी

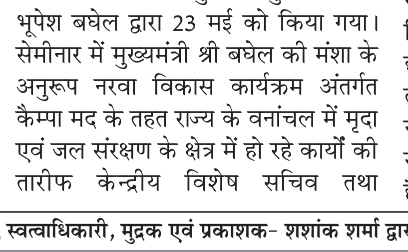

रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार में यह जानकारी दी गई। 25 मई तक आयोजित राष्ट्रीय सेमीनार का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 23 मई को किया गया। सेमीनार में मुख्यमंत्री श्री बघेल की मंशा के अनुरूप नरवा विकास कार्यक्रम अंतर्गत कैम्पा मद के तहत राज्य के वनांचल में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की तारीफ केन्द्रीय विशेष सचिव तथा महानिदेशक श्री चन्द्रप्रकाश गोयल ने भी की और इसे देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय बताया। कार्यशाला में वन मंत्री मोहम्मद अकबर, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, महानिदेशक एवं केन्द्रीय विशेष सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन चन्द्रप्रकाश गोयल, वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, केन्द्रीय कैम्पा के सीईओ सुभाष चन्द्र, प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्ही. श्रीनिवास राव तथा वानिकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में नरवा विकास कार्यक्रम के तहत कैम्पा मद अंतर्गत वनांचल स्थित नालों में काफी तादाद में भू-जल संरक्षण संबंधी कार्यो का तेजी से क्रियान्वयन जारी है। इससे वन क्षेत्रों के भू-जल स्तर में काफी सुधार दिखाई देने लगा है और वनवासियों सहित क्षेत्रवासियों को पेयजल, सिंचाई तथा निस्तारी आदि सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलने लगा है। साथ ही साथ इससे वन संरक्षण तथा संवर्धन के कार्यों को भी बढ़ावा मिला है। राज्य में इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को 'स्कॉच अवार्ड' के पर्यावरण श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ में गत चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी 'नरवा विकास' योजना के तहत वनांचल स्थित 6 हजार 395 नालों के लगभग 23 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्रों को उपचारित करते हुए विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण तेजी से किया जा रहा है।

ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना की सशक्त समिति बैठक सम्पन्न

रायपुर। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आई.टी विभाग के अंतर्गत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए गठित सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटीकरण परियोजना की अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य मंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी शामिल हुये। बैठक में जानकारी दी गई कि पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु प्रथम चरण में राज्य की 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में से 2028 समितियों का चयन किया गया है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कुल 55 करोड़ 70 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 33

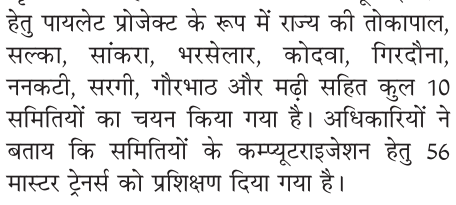

करोड़ 42 लाख केन्द्रांश और 22 करोड़ 28 लाख राज्यांश का है।

सहकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि साख सहकारी समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में राज्य की तोकापाल, सल्का, सांकरा, भरसेलार, कोदवा, गिरदौना, ननकटी, सरगी, गौरभाठ और मढ़ी सहित कुल 10 समितियों का चयन किया गया है। अधिकारियों ने बताय कि समितियों के कम्प्यूटराइजेशन हेतु 56 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया गया है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.